वर्ष 13 • अंक 29 • 8 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये
गुरुवार 26 मार्च 2020
कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 8
ई-कॉमर्स कंपनियां नहीं ले रहीं ऑर्डर

हर्षवर्द्धन पृष्ठ 4
टेलीमेडिसिन परामर्श पर दिशानिर्देश जारी

डॉलर रु. 76. 10 (बाजार बंद) | यूरो रु. 82. 50 (बाजार बंद) | सोना (10ग्राम) रु. 43250 ▲ 1172 रुपये | सेंसेक्स 28535. 80 ▲ 1861. 80 | निफ्टी 8317. 80 ▲ 516. 80 | निफ्टी फ्यूचर्स 8406. 50 ▲ 88. 60 | ब्रेंट क्रूड 25. 70 डॉलर ▼ 01. 30 डॉलर

एक नज़र

गृह मंत्रालय ने बंद के संबंध में जारी किए नए आदेश

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन (बंद) से छूट पाने वाले लोगों और सेवाओं के संबंध में बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों, पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही वन कर्मचारियों को इस बंद के दायरे से छूट दी गई है। इसके अलावा कुछ अन्य सेवाएं भी बंद की जद से बाहर रखी गई हैं। बंद के दौरान हर रोज दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें खुलेंगी।

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर प्रतिबंध

सरकार ने बुधवार को कोरोनावायरस के प्रकोप के मद्देनजर घरेलू बाजार में दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जानकारी दी गई। भारतीय चिकित्सा शोध परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध या पुष्ट मामलों में देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल की सिफारिश की थी।

गोएयर मार्च के वेतन में करेगी कटौती

गोएयर ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी ने विमानन क्षेत्र के राजस्व पर भारी असर डाला है, इसलिए कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के मार्च के वेतन में कटौती करेगी। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनय दूबे ने बुधवार को यह बात कही। गोएयर ने पहले ही लागत में कटौती के कुछ उपाय किए हैं। इससे पहले इंडिगो ने कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत तक की कटौती करने की घोषणा की थी। एयर इंडिया ने भी कर्मचारियों के भत्तों में कमी करने का ऐलान किया है। पृष्ठ 3

एनपीआर, जनगणना का पहला चरण स्थगित

कोरोनावायरस के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का अद्यतन और 2021 की जनगणना पहला चरण रोक दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। दोनों प्रक्रियाएं 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरी होनी थीं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जनगणना दो चरणों में पूरी होनी थी। पहले चरण में अप्रैल-सितंबर के दौरान मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना और 9-28 फरवरी के दौरान आबादी की गणना शामिल है।

बिजली के दाम तीन वर्षों के निचले स्तर पर

हाजिर बाजार में बिजली की दर बुधवार को तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण फैक्टरियों एवं कारोबारी प्रतिष्ठानों में बिजली की मांग कम हो गई है, जिस वजह से दरों में गिरावट देखी गई। लॉकडाउन के कारण बिजली की मांग 20 गीगावाट तक कम हो गई। आईईएक्स के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 2017 में हाजिर बाजार में बिजली का दाम प्रति यूनिट 52 पैसे तक कम हो गया, जो 2018 में बढ़कर 1.72 रुपये प्रति यूनिट हो गया। 2019 में इसमें 94 पैसे की कमी आई थी।

व्यापार गोष्ठी

मौजूदा हालात में कैसे थमे आर्थिक गिरावट?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या सरकार को जल्द करनी चाहिए राहत पैकेज की घोषणा

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो BSP Y और यदि न है तो BSP N लिखकर 57007 पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या कोरोना जैसे संकट से निपटने में पर्याप्त हैं देश में स्वास्थ्य सेवाएं?	हां	16.67%
	नहीं	83.33%

लॉकडाउन से छिना रोजगार तो याद आया गांव, घर-द्वार

बंदी की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से कई लोग अपने गांव जाने को मजबूर

आदिति फडणीस
नई दिल्ली, 25 मार्च

एक वक्त था जब मुश्ताक अंसारी को नोएडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में सुबह सात बजे शुरू होने वाली पहली पाली में काम करने के लिए सुबह-सुबह भागना पड़ता था। उनके पास नाश्ता करने का भी वक्त नहीं होता था। लेकिन अब कोई जल्दबाजी नहीं है। सुबह के दस बजे हैं और 25 साल के अंसारी आराम से बैठकर अचार और दही के साथ परांठे खा रहे हैं। उन्हें कहीं नहीं जाना है और उनके पास कोई काम नहीं है।

उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, 'मैं अभी मजे कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही मजे करने पड़ सकते हैं।' अंसारी का परिवार 30 साल पहले बिहार से नोएडा आया था। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद अंसारी को एसईजेड में नौकरी मिल गई जहां वह चीन की कंपनी पीसीटीपीएल में काम करते हैं। यह कंपनी पीवीसी शीट बनाती है जिसका इस्तेमाल सिम कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाने में होता है। पीसीटीपीएल के ग्राहकों में फ्रांस की दिग्गज दूरसंचार कंपनी सिस्कॉम है। यह बताते हुए अंसारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उनकी कंपनी की दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितनी अहम भूमिका है।

नोएडा एसईजेड में 400 इकाइयां हैं और वहां करीब एक लाख लोग काम करते हैं। देश में कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे 23 मार्च को बंद कर दिया था। अंसारी कहते हैं कि तब उनकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को वेतन देने के वादा किया था लेकिन अब क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जब चीन में कोविड-19 फैला था तो उन्होंने अपने सारे ऑर्डर यहां भेज दिए थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि साल के अंत में हमें अच्छा खासा बोनस मिलेगा क्योंकि बहुत सारा काम था। लेकिन अब मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अगर कंपनी की रफ्तार कम होती है और पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है, तो मैं यह उम्मीद कैसे करूं कि कंपनी मुझे वेतन देगी।

पेट्रोल पंप पर दिहाड़ी पर काम करने वाले महेंद्र कुमार और सूरजपुर में वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी मिंडा ऑटो में काम करने वाली हेमंत नागर के मन में इस तरह की कोई दुविधा नहीं है। हालांकि पेट्रोल पंप को जरूरी सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। कुमार और नागर पैदल ही घर जा रहे हैं क्योंकि बस और ट्रेन नहीं चल रही है। कुमार 400 किमी दूर कानपुर जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सब्जी या दूध के ट्रक में लिफ्ट लेकर वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। नागर को करीब 100 किमी दूर अलीगढ़ के करीब स्थित अपने घर तक पैदल ही जाना होगा। दोनों ने थोड़ा बहुत जरूरत का सामान अपने बैग में रखा है।

दिल्ली की एक गारमेंट फैक्टरी में काम करने वाली जीनत अब उत्तर प्रदेश के अपने गांव जाना चाह रही हैं। फोटो : सोमेश झा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को सलाह दी है कि 'जो जहां हैं, वहीं रहें' लेकिन कीमतों पर मोदीजी कैसे लगाम लगाएंगे? आटे का 10 किलो का जो पैकेट 260 रुपये में मिलता था वह 400 रुपये में मिल रहा है। आलू 40 रुपये किलो तक पहुंच गई है। टमाटर और प्याज 60 रुपये किलो मिल रहे हैं। जब काम होता है तो हमें महीने में 7,000 रुपये मिलते हैं। आजकल कोई काम नहीं है और न ही अनाज और पैसा है। इसलिए हम गांव जाएंगे और वहां खेती बाड़ी में मदद करेंगे। (शेष पृष्ठ 8 पर)

बड़े प्रोत्साहन का होगा ऐलान!

सरकार ला सकती है डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रोत्साहन पैकेज

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 25 मार्च

कोरोनावायरस से राष्ट्रव्यापी बंदी से मुकाबला करने के लिए सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोत्साहन पैकेज ला सकती है। दो जानकार सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी प्रोत्साहन पैकेज को अंतिम रूप नहीं दिया है और इस बारे में प्रधनमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच बातचीत चल रही है। सूत्रों ने नाम जाहिर नहीं करने पर कहा कि अभी इस मसले पर चर्चा की जा रही है।

- प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच चर्चा
- सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है आरबीआई
- उधारी योजना को भी बढ़ाने पर हो सकता है विचार
- गरीबों के खाते में सीधे पैसे दे सकती है सरकार
- बंदी से प्रभावित कारोबारों को मिल सकती है मदद

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रोत्साहन योजना 2.3 लाख करोड़ रुपये तक का हो सकता है लेकिन अभी इस पर चर्चा चल रही है और अंतिम आंकड़े तय नहीं हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि पैकेज की घोषणा इस सप्ताह के अंत तक की जा सकती है। इसके तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे और साथ ही बंदी से प्रभावित होने वाले कारोबारों को मदद दी जाएगी।

कोरोनावायरस से प्रसार को सीमित करने के लिए सरकार ने मंगलवार को 21 दिनों के लिए देश भर में बंदी का ऐलान किया था। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 562 पहुंच गई है, वहीं 9 लोगों की इससे मौत हुई है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार अपनी उधारी योजना का भी विस्तार कर सकती है। फिलहाल 7.8 लाख करोड़ रुपये सकल उधारी की योजना बनाई गई थी जिसे बढ़ाया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने को कहा है। मुद्रास्फीति बढ़ने के डर से केंद्रीय बैंक ने एक दशक से इसकी खरीदारी नहीं की है। सरकारी अधिकारी ने कहा, 'आरबीआई भी दुनिया के अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह बॉन्ड खरीद सकता है।'

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगर नकदी की किल्लत होती है तो सरकार केंद्रीय बैंक के ओवरड्राफ्ट सुविधा का भी उपयोग कर सकती है। इस बारे में जानकारी के लिए संपर्क करने पर वित्त मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की। आरबीआई को भेजे गए ईमेल का भी कोई जवाब नहीं आया।

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कर दायर करने की समयसीमा बढ़ाने और दिवालिया प्रक्रिया में भेजे जाने के लिए डिफॉल्ट की तय सीमा को भी बढ़ा दिया था।

प्रति व्यक्ति मिलेगा दो किलो अतिरिक्त अनाज

कोरोना की वजह से देश भर में लगी पाबंदियों के बीच आम लागों तक राशन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने बुधवार को राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का मासिक कोटा दो किलोग्राम बढ़ाकर सात किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 80 करोड़ लोगों को 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गेहूं की कीमत 27 रुपये किलो है, जो दो रुपये किलो की रियायती दर पर दी जाएगी और 32 रुपये किलो वाले चावल की आपूर्ति 3 प्रति किलो की दर से की जाएगी। *भाषा*

राहत की उम्मीद से बाजार को दम

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 25 मार्च

अमेरिका में 2 लाख करोड़ डॉलर के प्रोत्साहन विधेयक पर सहमति बनने से भारतीय बाजार में भी आज 7 फीसदी की जोरदार तेजी देखी गई। निवेशकों को उम्मीद है कि भारत सरकार भी भारी-भरकम पैकेज ला सकती है, जिससे लिवाली को दम मिला। सेंसेक्स 1,862 अंक चढ़कर 28,536 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 497 अंक चढ़कर 8,298 पर बंद हुआ। मई 2009 के बाद सूचकांकों में एक दिन में आई यह सबसे बड़ी उछाल है।

निफ्टी 50

इनमें आई तेजी

	25 मार्च, 2020 कीमत ~	वृद्धि (%)
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,082.3	14.7
ग्रासिम इंडस्ट्रीज	451.4	12.8
कोटक महिंद्रा बैंक	1,290.2	11.9
यूपीएल	292.8	11.7
एचडीएफसी बैंक	856.8	11.6

स्रोत : एक्सचेंज/ब्लूमबर्ग
संकलन : बीएस रिसर्च

अधिकांश एशियाई और यूरोपी बाजारों में भी तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी डाऊ जोंस मंगलवार को 11 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ था। अमेकिरा के 2 अरब डॉलर के पैकेज को इस संकट की घड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।

राष्ट्रव्यापी 21 दिनों की बंदी की घोषणा के बावजूद घरेलू बाजार में तेजी आई है। बाजार के भागीदारों ने इस कदम का स्वागत किया लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार को राहत उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए। वेलेंटिस एडवाइजर्स के संस्थापक ज्योतिवर्धन जयपुरिया ने कहा, 'हम सरकार से प्रोत्साहन पैकेज मिलने का इंतजार कर रहे हैं। (शेष पृष्ठ 3 पर)

जालंधर में लोगों के घर तक पहुंची दवाएं

बीएस संवाददाता
जालंधर, 25 मार्च

पंजाब में निषेधाज्ञा के बीच जालंधर के लोगों को जिला प्रशासन ने बुधवार को 93,000 लीटर दूध की आपूर्ति की। स्थानीय प्रशासन ने लोगों के बीच दवाओं और 1,100 क्विंटल फल एवं सब्जियों की भी आपूर्ति की।

जिले के उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को नागरिकों को सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मिल्कफेड के लोगों ने जालंधर के निवासियों को 93,000 लीटर दूध की आपूर्ति की। जिले में हरेक जगह वर्का के अधिकृत डीलरों के माध्यम से दूध की आपूर्ति की गई। इससे पहले वर्का ने मंगलवार को 1,07,000 लीटर दूध की आपूर्ति की थी।

इसी तरह, दवा नियंत्रक अधिकारी सुश्री कमल कंबोज ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कुछ अन्य बीमारियों से जुड़ी दवाओं की आपूर्ति की। फगवाड़ा गेट में सहायक पुलिस आयुक्त विमल कांत ने एक महिला के फोन कॉल के बाद उन तक दवा पहुंचाई। इसी तरह, जालंधर के जिला मंडी अधिकारी ने लोगों के बीच 1,100 क्विंटल फल एवं सब्जियों की आपूर्ति की।

इस बीच, उपायुक्त ने कहा कि वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। उनहोंने कहा कि सभी आवश्यक सेवाएं लोगों तक तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह उनके साथ है।

ठप पड़ रहे देश के विनिर्माण संयंत्र

ईशिता आयान दत्त और अभिषेक रक्षित
कोलकाता/मुंबई, 25 मार्च

भारत का विनिर्माण क्षेत्र धीरे-धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। कोरोनावायरस से देश में आए भूचाल के बीच कंपनियां श्रमिकों, कच्चे माल और अन्य सुविधाओं के अभाव में अपने उत्पादन संयंत्र बंद कर रही हैं। देश ही नहीं कोरोना के कहर से दुनिया के दूसरे देशों में भी उनके संयंत्रों में परिचालन ठप हो रहा है। आदित्य बिड़ला समूह नियंत्रित हिंडाल्को ने कहा है कि राज्य सरकारों के निर्देशों के बाद इसने एल्युमीनियम और तांबा विनिर्माण संयंत्रों में अस्थायी तौर पर उत्पादन रोक दिया है। कंपनी ने कहा कि लोगों के बीच सामाजिक संपर्क कम करने की सरकार की अपील के बाद कम से कम कर्मचारियों के साथ परिचालन हो रहा है। अमेरिका में हिंडाल्कों की सहायक कंपनी नोवेलिस ने भी आंशिक रूप से परिचालन रोक दिया है। वहां अमेरिकी वाहन कंपनियों ने कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर काम रोक दिया है। आदित्य बिड़ला समूह की दूसरी कंपनियों ग्रासिम और अल्ट्राटेक के कुछ संयंत्रों में भी सरकारी आदेश के बाद काम-काज रोक दिया गया है।

हिंडाल्को
कुछ एल्युमीनियम और कॉपर विनिर्माण संयंत्र बंद, नोवेलिस ने भी अमेरिका में अपने कुछ संयंत्रों को आंशिक तौर पर किया बंद

ग्रासिम
लॉकडाउन को देखते हुए कई जगहों पर परिचालन बंद किया

अल्ट्राटेक सीमेंट
भारत में कई जगहों पर परिचालन बंद किया

जिंदल स्टेनलेस
ओडिशा के जाजपुर में संयंत्र किया बंद

कल्याणी स्टील
कर्नाटक में बंद किया उत्पादन

एवरेडी इंडस्ट्रीज
सभी विनिर्माण संयंत्र, कॉरपोरेट एवं बिक्री कार्यालय किए बंद

दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने इंडोनेशिया में वहां की सरकार के आदेश के बाद अपने संयंत्र में उत्पादन बंद कर दिया है। इसी तरह, जिंदल स्टेनलेस ने कहा है कि ओडिशा के जाजपुर में उसके संयंत्रों में तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सल केबल्स ने भी सतना विनिर्माण संयंत्र में काम रोकने की बात कही है। कंपनी की गोवा इकाई में 22 मार्च के सुबह से ही परिचालन बंद है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पीऐंडजी हेल्थ ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों की तरफ से बंद के आदेश के बाद भारत में विभिन्न जगहों, संयंत्रों और वितरण केंद्रों में परिचालन प्रभावित हुआ है।

कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का परिवहन प्रभावित हो रहा है। उदाहरण के लिए इमामी समूह की कंपनी इमामी एग्रोटेक के राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संयंत्र है और वहां से उत्तर एवं दक्षिण भारत के तमाम बड़े बाजारों में खाद्य तेल की आपूर्ति करते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसकी कुछ उपस्थिति है। सीमाएं बंद होने के कारण राजस्थान और आंध्र प्रदेश सरकारों ने इमामी को संयंत्र बंद करने के आदेश दिए हैं। (शेष पृष्ठ 8 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

रिलायंस इंडस्ट्रीज

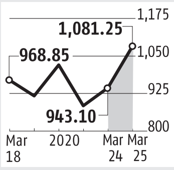

अमेरिकी दिग्गज फेसबुक की नजर रिलायंस जियो के 10 फीसदी हिस्से पर

₹ 943.10 पिछला बंद भाव
₹ 1,081.25 आज का बंद भाव
▲ 14.65 %

आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस

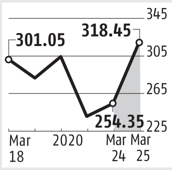

एसऐंडपी बीएसई-500 इंडेक्स में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर

₹ 254.35 पिछला बंद भाव
₹ 318.45 आज का बंद भाव
▲ 25.20 %

मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर

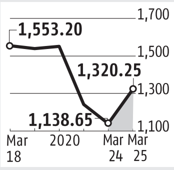

लंबी अअधि के मजबूत बढ़त परिदृश्य के कारण ब्रोकरेज ने किया अपग्रेड

₹ 1,138.65 पिछला बंद भाव
₹ 1,320.25 आज का बंद भाव
▲ 15.95 %

एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक

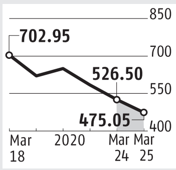

शेयर पर लगातार तीसरे दिन लगा 10 फीसदी का लोअर सर्किट

₹ 526.50 पिछला बंद भाव
₹ 475.05 आज का बंद भाव
▼ 9.77 %

बंधन बैंक

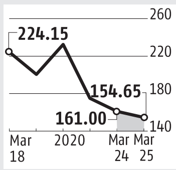

बाजार पूंजीकरण 25,000 करोड़ रुपये से नीचे, एक महीने में 62 फीसदी टूटा

₹ 161.00 पिछला बंद भाव
₹ 154.65 आज का बंद भाव
▼ 3.94 %

संक्षेप में

इंडिगो ने सरकार को विमानों की पेशकश की

इंडिगो ने बुधवार को कहा कि उसने केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में दवाओं, उपकरणों, राहत सामग्री की ढुलाई के लिए अपने विमान और चालक दल के सदस्यों का उपयोग करने की पेशकश की है। देशभर में लॉकडाउन के कारण सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें निलंबित हैं, जिसके चलते इंडिगो के 250 से अधिक विमान फिलहाल खड़े हुए हैं। एयरलाइन ने एक प्रेस में जारी बयान में कहा, इंडिगो ने देश में कोरोना वायरस से लड़ाई में सहयोग करने के लिए भारत सरकार को अपने संसाधनों, विमानों और चालक दल से सदस्यों का उपयोग करने की पेशकश की है। *भाषा*

दो दिन की तेजी से 6.63 लाख करोड़ रु. का इजाफा

शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी तेजी से निवेशकों की संपत्ति 6,63,240.78 करोड़ रुपये बढ़ी। कोरोनावायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है। बीएसई का तीस शेयरों वाला सेंसेक्स बुधवार को 1,861.75 अंक यानी 6.98 प्रतिशत मजबूत होकर 28,535.78 अंक पर पहुंच गया। इससे पिछले दिन के कारोबार में यह 692.79 अंक यानी 2.67 प्रतिशत मजबूत होकर 26,674.03 अंक पर बंद हुआ था। शेयर बाजार में इस जोरदार तेजी से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पिछले दो दिनों में 6,63,240.78 करोड़ रुपये बढ़कर 1,08,50,177.06 करोड़ रुपये पहुंच गया। *भाषा*

दुनियाभर में अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास तेज

दुनियाभर की सरकारें और केंद्रीय बैंक इन दिनों अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कोरोनावायरस के गंभीर प्रभाव से बचाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। ये केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए नई मुद्राओं का प्रकाशन, भारी व्यय करना, बड़े पैमाने पर रिण की गारंटी देना, कर रियायत देने और कर्मचारियों कामगारों को सीधे भुगतान जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। एएफपी ने इस संबंध में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 के मद्देनजर उठाए जा रहे कदमों का सर्वेक्षण किया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में सीनेट नेताओं और व्हाइट हाउस के बीच बुधवार को अर्थव्यवस्था को 2,000 अरब डॉलर का प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने के प्रावधान वाले विधेयक पर सहमति बन गई। इस पैकेज के जरयि अमेरिकियों के हाथ में सीधे नकदी पहुंचाई जाएगी, छोटे कारोबारियों को अनुदान मिलेगा और बड़ी कंपनियाको अरबों डालर का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। *एजेंसी*

बदल जाएगी मनोरंजन की खपत

सामाजिक दूरी, संचारी रोगों की आशंका से भविष्य में घटेगा थिएटर का आकर्षण

पवन लाल
मुंबई, 25 मार्च

कपिल देव की जीवनी पर आधारित रणवीर सिंह और दीपिका पडुकोण अभिनीत फिल्म 83 (अप्रैल में रिलीज) या अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ अभिनीत फिल्म सूर्यवंशी (मार्च में रिलीज) को देखने के लिए उत्सुक फिल्म प्रेमियों को उनकी स्क्रीनिंग में अनिश्चितकालीन देरी के कारण निराश होना पड़ सकता है। देश को करोनावायरस महामारी से निपटने के लिए सिनेमा मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया है। अगर एक-दो महीने तक यही स्थिति रही तो भविष्य में थिएटर जाकर फिल्म देखने का तरीका बदल सकता है।

इरोस इंटरनैशनल के चेयरमैन एवं सीईओ किशोर लूला ने कहा कि सोशल डिस्टैंसिंग के कारण निस्संदेह भारतीय फिल्म बॉक्स ऑफिस का राजस्व घटेगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिनेमा थिएटर कारोबार में सुदृढ़ीकरण के कारण चार प्रमुख कंपनियां सामने आई हैं जिनमें पीवीआर, आईनॉक्स, कार्निवल सिनेमा और सिनेपोलिस शामिल हैं। भारत में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर इन्हीं कंपनियों का वर्चस्व है। सबसे बड़ी कंपनी पीवीआर के पास 60 शहरों में 152 संपत्तियां और 706 स्क्रीन मौजूद हैं। फिलहाल वे सभी अनिश्चित काल के लिए बंद हैं।

अपनी फिल्मों के लिए चीनी वितरकों के साथ भागीदारी करने वाली लूला का कहना है कि उन्हें मिली प्रतिपुष्टि के अनुसार चीन में सिनेमाघरों को चीन में एक दो महीने खुल जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'सिनेमाघरों के खुलने के बाद संचालकों के लिए नया मानदंड यह होगा कि 25 फीसदी क्षमता पर ही टिकट बिके ताकि किसी संक्रामक बीमारी के जोखिम से बचा जा सके।' उन्होंने कहा कि ऐसा वैश्विक स्तर पर भी दिख सकता सकता है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर महामारी फैलने के बाद लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करते हैं।

एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि मनोरंजन की खपत हमेशा के लिए बदल जाएगी क्योंकि इस महामारी के लिए कोई टीका या इलाज फिलहाल नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी लंबे समय तक सिनेमाघरों में नहीं जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो यह एक बदली हुई आदत होगी और दर्शकों की आवक आधे से अधिक घट जाएगी। इस महामारी की रोकथाम में दो से तीन महीने लग सकते हैं और जब स्थिति सामान्य होगी तो दर्शकों की आवक में कमी का जोखिम होगा। इससे थिएटर मूवी को जबरदस्त झटका लगेगा।

वूट एडवरटाइजिंग प्लेटफॉर्म के बिजनेस हेड आकाश बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन सामग्री प्लेटफॉर्म वूट के लिए प्रति उपयोगकर्ता औसत दैनिक सत्रों में 25 फीसदी की तेजी दर्ज की है। वूट के एक तिहाई से ज्यादा ग्राहक दिन में कम से कम पांच बार लगातार एक घंटे से ज्यादा समय तक ऐप को बार-बार शेयर करते रहे हैं। बनर्जी ने कहा, 'हमारे कुछ शो सुपरहिट हो गए हैं और शीर्ष 15 शो की खपत में 40 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि 8 इंच, 12 इंच या 50 इंच की स्क्रीन एक बड़े सिनेमा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती और दर्शकों को थिएटर जैसा अनुभव नहीं दे सकती।'

कोटक इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग के एनबीओसी यानी नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के प्रमुख रुझानों से दो प्रवृत्तियों का पता चलता है- युवा सितारों वाली 100 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये को पार करने वाली फिल्मों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान शीर्ष 5 फिल्मों ने बड़े सितारों (तीनों खान) के लुभावने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के कारण एनबीओसी में कैसे वृद्धि हुई। ठीक उसी समय सितारों की एक नया समूह तैयार हुआ जिसमें रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार जैसे अभिनेता शामिल हैं।

दूरसंचार की तैयारी

- सबसे बड़ी कंपनी पीवीआर के पास 60 शहरों में 152 संपत्तियां और 706 स्क्रीन मौजूद हैं। फिलहाल वे सभी अनिश्चित काल के लिए बंद हैं
- अगर एक-दो महीने तक यही स्थिति रही तो भविष्य में थिएटर जाकर फिल्म देखने का तरीका बदल सकता है

वेंटिलेटर उत्पादन के लिए कार फर्मों के संयंत्र का इस्तेमाल हो

अरिंदम मजूमदार और सोहिनी दास
नई दिल्ली/मुंबई, 25 मार्च

सरकार ने सभी वाहन निर्माताओं को अपने संयंत्रों में वेंटिलेटर व अन्य चिकित्सकीय सामग्री के उत्पादन की संभावना तलाशने को कहा है, जिसकी जरूरत कोरोनावायरस से लड़ने में आवश्यक है। समझा जाता है कि आनंद महिंद्रा की अगुआई वाली महिंद्रा ऐंड महिंद्रा बेंगलूरु की वेंटिलेटर निर्यातक स्केनरे टेक्नोलॉजिज के साथ बातचीत के अंतिम चरण में है। टाटा मसूह की टाटा मोटर्स की भी मैसूर की विनिर्माता के साथ बातचीत के अंतिम चरण में है ताकि वेंटिलेटर का विनिर्माण बढ़ाया जा सके।

अहम वाहन निर्माताओं को भेजे संदेश में भारी उद्योग मंत्रालय ने वाहन कंपनियों के विनिर्माण संयंत्र और श्रम शक्ति का इस्तोल वेंटिलेटर में करने की संभावना तलाशने को कहा है। सूत्रों ने कहा कि चार अहम कंपनियों मारुति सुजूकी, एमऐंडएम, टाटा मोटर्स और हुंडई के साथ बैठक के बाद यह संदेश भेजा गया। अमेरिका में फोर्ड मोटर्स ने 3एम कंपनी व जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर रेस्पिरेटर और वेंटिलेटर के विनिर्माण पर काम शुरू किया है। पिछले 48 घंटे में देश में वेंटिलेटर निर्माण पर सरकार काफी हाथ-पांव मार रही है। यूरोप से आयात करीब-करीब बंद होने के कारण भारत को वेंटिलेटर मशीन की क्षमता तत्काल बनाने की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल आईसीयू में मरीजों का ध्यान रखने में होता है।

ब्रुकिंग्स इंस्टिट्यूशन के अध्ययन के मुताबिक, 15 मई तक भारत को करीब 1.10 लाख से 2.20 लाख वेंटिलेटर की जरूरत होगी, वहीं अभी यहां सिर्फ 17,850 से 25,556 इकाइयां हैं। उद्योग के एक जानकार ने कहा, सरकार ने वस्तुत: वॉर रूम बनाया है और वास्तविक समय के आधार पर काम हो रहा है। वास्तव में कुछ संयुक्त सचिव विनिर्माताओं के साथ व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़े हैं। सरकार और उद्योग देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। मारुति सुजूकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा, सरकार वेंटिलेटर की बड़ी जरूरत का अनुमान लगा रही है। उन्होंने हमसे संपर्क किया है और वेंटिलेटर बनाने की संभावना तलाशने पर बातचीत की है। हमारी टीम हर संभावना पर नजर डाल रही है। हम एक यो दो दिन में जवाब के साथ सामने आएंगे।

टाटा समूह वेंटिलेटर विनिर्माण के लिए संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है। हम इस पर प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं

एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा संस

महिंद्रा समूह तत्काल इस पर काम शुरू करेगा कि कैसे हमारे संयंत्रों में वेंटिलेटर का विनिर्माण हो सकता है

आनंद महिंद्रा, सीईओ, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा

एचडी से एसडी की ओर डिजिटल उद्योग

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 25 मार्च

कोरोनावायरस के फैलने के मद्देनजर कंपनियों द्वारा घर से काम करने पर जोर दिए जाने के कारण इंटरनेट सेवाओं की मांग बढ़ गई है। ऐसे में डिजिटल उद्योग ने 14 अप्रैल तक अस्थायी तौर पर केवल स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) स्ट्रीमिंग सेवाओं की पेशकश करने का निर्णय लिया है।

सूत्रों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में डेटा की खपत 15 से 20 फीसदी तक बढ़ गई है और एचडी (हाई डेफिनिशन) डेटा खपत के लिए 6 से 7 फीसदी अधिक बैंडविड्थ की जरूरत होती है। स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर की डिजिटल उद्योग के वरिष्ठ लोगों के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिजिटल उद्योग ने देश और उपभोक्ता के व्यापक हित में तुरंत पहल करने और सेल्युलर नेटवर्क की मजबूती सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। यह कदम मोबाइल इंटरनेट की खपत में जबरदस्त उछाल के कारण सेल्युलर नेटवर्क के बुनियादी ढांचे पर संभावित प्रभाव के मद्देनजर उठाया गया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोग इन दिनों अपने घरों में रह रहे हैं, जिससे इंटरनेट की खपत बढ़ गई है।

कंपनियों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में पूरी तरह लॉकडाउन किए जाने और लोगों को अपने-अपने घरों में रहने की अपील की गई है। इससे मोबाइल इंटरनेट की खपत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। दूरसंचार नेटवर्क पर इसके प्रभाव को लेकर सरकार और दूरसंचार ऑपरेटर चिंतित हैं।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिजिटल उद्योग इस चुनौती से पूरी तरह अवगत है। उद्योग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी नागरिक मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर सकें। इसी उद्देश्य से डिजिटल उद्योग के प्रमुख हितधारकों के साथ स्टार ऐंड डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष ने मंगलवार को एक बैठक आयोजित की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित इस बैठक में सोनी के एनपी सिंह, गूगल के संजय गुप्ता, फेसबुक के अजित मोहन, वायकॉम-18 के सुधांशु वत्स, एमेजॉन प्राइम वीडियो के गौरव गांधी, जी के पुनीत गोयनका, टिकटॉक के निखिल गांधी, नेटफ्लिक्स की अंबिका खुराना, एमएक्स प्लेयर के करण बेदी और हॉटस्टार के वरुण नारंग मौजूद थे।

ब्याज भुगतान टालने से संकट होगा कम

देव चटर्जी और श्रीपाद ऑटे
मुंबई, 25 मार्च

देश में ज्यादा कर्ज से फंसी कंपनियों के लिए अपने कर्ज पर ब्याज का भुगतान करने में मुश्किल आएगी। प्रमुख वित्तीय अधिकारियों और विश्लेषकों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार अगले छह महीनों के लिए ब्याज भुगतान टालने पर रोक नहीं लगाती है तब ये कंपनियां भुगतान नहीं कर पाएंगी।

विश्लेषकों का कहना है कि रिलायंस, लार्सन ऐंड टुब्रो और टाटा स्टील जैसी कुछ कंपनियां पर्याप्त नकदी की वजह से अपनी देनदारियों को पूरा कर पाएंगी जबकि दूरसंचार, विमानन कंपनियों, रियल एस्टेट और वाहन कंपनियों को ब्याज देनदारियों में मुश्किल आएगी। ब्याज भुगतान पर रोक से कंपनियों को अपने आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करने और चक्र को चालू रखने में मदद मिलेगी। ब्याज भुगतान को फिलहाल स्थगित करने से कंपनियों को अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में मदद मिलेगी और बाकी प्रक्रिया जारी रखी जा सकेगी।

जेएसडब्ल्यू स्टील के समूह प्रबंध निदेशक शेषागिरी राव ने कहा, 'नकदी के अंतर को पूरा करने और पुनर्भुगतान तथा ब्याज को कम से कम छह महीने तक रोकने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की फंडिंग की जानी चाहिए।'

बजाज ग्रुप के समूह वित्त निदेशक प्रबल बनर्जी ने कहा, 'कोरोनावायरस (कोविड-19) की वजह से जमीनी स्तर पर स्थिति बहुत खराब है। कंपनियों को मूलधन भुगतान के लिए दो साल और अगले छह महीने के लिए ब्याज भुगतान पर रोक होनी चाहिए। ब्याज दर का समायोजन कर ऋणों के शुद्ध वर्तमान मूल्य की भी सुरक्षा की जानी चाहिए, ताकि बैंकों को कोई नुकसान न हो।'

कंपनियों को मिलेगी राहत!

विश्लेषकों का कहना है कि कई क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है क्योंकि कोविड-19 महामारी फैलने की वजह से देश भर में बंदी के कारण उनकी बिक्री घट गई है। इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड एडवाइजरी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जी चोक्कालिंगम ने बताया, 'रियल एस्टेट, वाहन जैसे क्षेत्रों में भी कार्यशील पूंजी के फंसने और कम कमाई का दबाव भी देखने को मिलेगा।'

सामान्य कारोबारी चक्र में भी शुद्ध बिक्री का एक-तिहाई या करीब 33 फीसदी हिस्सा इन्वेंट्री और कर्जदारों का होता है और यह रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में ज्यादा ही करीब 80 फीसदी तक होता है।

चोक्कालिंगम आगाह करते हुए कहते हैं, 'जिन कंपनियों ने कर्ज लेकर यह उम्मीद की थी कि वे ब्याज भुगतान से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाएंगी और प्रवर्तकों से ज्यादा वादा करने वाली कंपनियों के लिए मुश्किल समय होगा। इसकी वजह से कुछ मामलों में परिसंपत्तियों की बिक्री और कर्ज निपटाने पर ही जोर देना पड़ेगा।'

इंडियानिवेश के प्रमुख (संस्थागत इक्विटीज) विनय पंडित ने कहा, 'अगर मौजूदा बंदी अगली तिमाही तक भी जारी रही तो जो कंपनियां इक्विटी के मुकाबले ज्यादा कर्ज लेकर बैठी हैं उन्हें दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उत्पादन/आपूर्ति करने में असमर्थता और मांग में कमी से उन कंपनियों की वित्तीय सेहत पर प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने उधारी वाली पूंजी से ज्यादा मुनाफा कमाने की रणनीति बनाई थी। मौजूदा बंदी से मुनाफे पर भी असर पड़ेगा जहां तयशुदा लागत अधिक है। कंपनियां और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में वेरिएबल लागत (जहां उत्पादन के स्तर के साथ लागत में अंतर आता है) 80 फीसदी है उस पर कम असर देखने को मिलेगा।'

पंडित ने कहा, 'सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-निस्पादित परिसंपत्तियों (फंसे कर्ज) की पहचान करने में थोड़ी ढील देने पर विचार करना चाहिए जिससे कंपनियों, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर दबाव कम होगा।'

(साथ में कृष्ण कांत)

बीएस बातचीत

125 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले वाहन उतारेगी सुजूकी

सुजूकी मोटरसाइकल इंडिया की देसी बिक्री अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच छह फीसदी बढ़कर 6,51,293 वाहन हो गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 6,10,091 वाहन रही थी जबकि उद्योग में मांग सुस्त रही। सायम के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहिया में फर्म की बाजार हिस्सेदारी इस अवधि में 3.09 फीसदी से बढ़कर 3.94 फीसदी हो गई।

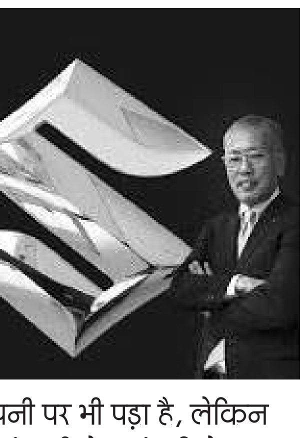

कोरोनावायरस के प्रसार का असर कंपनी पर भी पड़ा है, लेकिन **टी ई नरसिम्हन** को दिए साक्षात्कार में कंपनी के प्रबंध निदेशक **कोईचिरो हिराओ** ने कहा कि कंपनी की योजना भारत में अपना पोर्टफोलियो मजबूत बनाने की है। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

कोविड-19 ने आपके विनिर्माण पर कितना असर डाला है? क्या इससे पेशकश में देर होगी?

हां, निस्चित तौर पर। सुजूकी ने अगले आदेश तक हरियाणा में विनिर्माण संयंत्र में उत्पादन रोक दिया है। हमने अपने कर्मचारियों की सेहत सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं और वैसे कर्मियों व सहायकों को घर से काम करने की सलाह दी है जो आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़े हैं।

पूरा दोपहिया बाजार गिर रहा है, ऐसे में सुजूकी ने बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में कैसे इजाफा कर लिया?

सुजूकी मोटरसाइकल की बढ़त की रफ्तार की वजह प्राथमिक और द्वितीयक नेटवर्क में इजाफा है। हालांकि इससे न सिर्फ विस्तार हुआ बल्कि हमारे ज्यादातर मजबूत बाजारों में भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसकी वजह ब्रांड की बढ़ती स्वीकार्यता और ग्राहकों के साथ डीलरों का मजबूत जुड़ाव है। हमारे हर वाहन बाजार में बढ़त हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूती में बड़ा योगदान स्कूटर बाजार में हमारी बढ़ती भागीदारी है। सुजूकी एक्सेस 125 तेजी से इस श्रेणी की अग्रणी वाहन के तौर पर उभर रही है।

शहरी-ग्रामीण बिक्री का गणित कैसा है?

हम ग्रामीण और शहरी ग्राहकों के बीच भेद नहीं करते। इसके बजाय हम किसी कास इलाके के लिए ब्रांड विकसित करने को प्राथमिकता देते हैं, जो स्कूटर और प्रीमियम मोटरसाइकल को लेकर ग्राहकों की प्राथमिकता पर आधारित होती है। हम लगातार अपना प्रसार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मजबूत बाजार दक्षिण व पश्चिम में हैं।

सुजूकी की उत्पाद रणनीति क्या है? क्या वह सिर्फ स्कूटर पर ध्यान दे रही है या फिर बाइक पर भी?

वैश्विक स्तर पर सुजूकी प्रदर्शन केंद्रित मोटरसाइकल के लिए मशहूर है। इसके अतिरिक्त हमारा मानना है कि भारतीय ग्राहकों की प्राथमिकता अच्छे प्रदर्शन वाले मोटरसाइकल की तरफ बढ़ रही है। अपनी आधारभूत क्षमता के आधार पर हमारा मानना है कि हम इस मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। मोटरसाइकल पोर्टफोलियो मजबूत करने के लिए हमने सुजूकी जिक्सर 250 के साथ इस वित्त वर्ष में 250 सीसी के क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हमारी योजना समय के साथ 125सीसी से ज्यादा क्षमता वाले नए स्कूटर और मोटरसाइकल उतारने की है। हम एसएमसी जापान के साथ भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया विकसित करने पर काम कर रहे हैं।

बाइक और स्कूटर का अनुपात कितना है?

अभी हमारा स्कूटर और मोटरसाइकल करीब 90:10 में विभाजित है। इस साल जिक्सर सीरीज के सभी नए वाहन उतारे जाने और हमारी कोशिश के साथ हालांकि हमारा इरादा इस अनुपात को अगले वित्त वर्ष में 80:20 पर लाने का है।

लॉकडाउन से बाजार में कारोबार घटा

बाजार नियामक सेबी की सख्ती, कीमतों में गिरावट से भी कारोबार पर पड़ा दबाव। बाजार में कमजोर धारणा से निवेशकों की संख्या में भी भारी कमी आई है

समी मोडक
मुंबई, 25 मार्च

भले ही शेयर बाजार देशव्यापी लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें कारोबारी गतिविधि काफी घट गई है। इस सप्ताह के लिए वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) सेगमेंट के लिए औसत दैनिक कारोबार सालाना औसत के मुकाबले 66 प्रतिशत घटा है।

बाजार कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन और बाजार नियामक सेबी द्वारा हाल में बरती गई सख्ती भी इसके लिए जिम्मेदार है। ट्रेडिंग कारोबार में गिरावट की एक वजह कुछ खास प्रतिभूतियों में आई भारी कमी भी है। बाजार कारोबारियों का कहना है कि अनुबंध के सौदों की संख्या में कमी आई है और कारोबार सामान्य के मुकाबले 20 प्रतिशत तक घटा है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज में डेरिवेटिव्स एवं तकनीकी शोध प्रमुख चंदन तपाड़िया का कहना है, 'कारोबार में गिरावट कई कारकों की वजह से आई है। बाजार में कमजोरी से निवेशक धारणा प्रभावित हुई है और इससे निवेशकों की संख्या में भी कमी आई है। इसके अलावा, देशव्यापी लॉकडाउन से परिचालन में समस्याएं भी बढ़ी हैं। तीसरी बात, सेबी की सख्ती का भी इसमें योगदान रहा है।'

बुधवार को एफऐंडओ कारोबार 6.8 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया जो विश्लेषकों के अनुसार निपटान दिन से पूर्व के लिए असामान्य रूप से कम था। जनवरी और फरवरी में, ट्रेडिंग की मात्रा डेरिवेटिव एक्सपायरी से एक दिन पहले 17 लाख करोड़ रुपये और 19 लाख करोड़ रुपये पर दर्ज की गई थी।

बाजार कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कई ब्रोकर घर से काम कर रहे हैं और इसलिए वे उचित स्तरों पर परिचालन में सक्षम नहीं हैं।

उनका यह भी कहना है कि ब्रोकरों ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ने की वजह से जोखिम वाले दांव को प्रोत्साहित करना बंद कर दिया है।

एक कारोबारी ने कहा, 'शुरू में ब्रोकर अपने ग्राहकों को जोखिम के साथ परिचालन करने की अनुमति देते थे। मौजूदा समय में कई ब्रोकर ऊंचे उतार-चढ़ाव की वजह से इसे लेकर सतर्क हैं।'

बाजार में उतार-चढ़ाव का पैमाना इंडिया वीआईएक्स सूचकांक मंगलवार को 86.6 के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर बंद हुआ, जो 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दर्ज किए गए स्तरों से ज्यादा है।

एक्सपायरी वाला सप्ताह होने के बाद भी डेरिवेटिव में कमी

दैनिक औसत (करोड़ रुपये)	नकद	डेरिवेटिव
इस सप्ताह	40,876	5,55,372
साल की शुरुआत से अब तक	43,328	16,42,805
परिवर्तन (प्रतिशत)	-6	-66

स्रोत : एक्सचेंज

बाजार में उतार-चढ़ाव घटाने के प्रयास में, सेबी ने शुक्रवार को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए नियम सख्त बनाए थे। सेबी द्वारा घोषित बदलावों में ज्यादा उतार-चढ़ाव वाले शेयरों के लिए बाजार-आधारित पोजीशन सीमा, मार्जिन और जुर्माने में वृद्धि शामिल है। ये बदलाव सोमवार से प्रभावी हैं।

उद्योग के कारोबारियों द्वारा उठाया गया अन्य मुद्दा भुगतान का संग्रह था। एक कारोबारी ने कहा, 'बड़ी तादाद में कारोबारी अभी भी चेक में सौदे करते हैं। लॉकडाउन की वजह से, चेक मंगाने और उन्हें भुनाने में सक्षम नहीं हैं जिससे भी कारोबार प्रभावित हो सकता है।'

हालांकि सरकारी अधिकारियों ने शेयर बाजार व्यवस्था से जुड़ी कंपनियों को लॉकडाउन से अलग रखा है, लेकिन कई कारोबारियों ने ऑफिस आने में समस्याएं होने की शिकायत की है। मंगलवार को, केंद्र सरकार ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। हालांकि मुंबई (ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे ज्यादा योगदान) में लॉकडाउन पिछले सप्ताह से ही लागू था। एडलवाइस सिक्योरिटीज के प्रमुख (अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च) योगेश राडके ने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन की वजह से कारोबार में और ज्यादा कमी आ सकती है।

इक्रा ने कहा, येस बैंक को एक-दो साल में होगी 13,000 करोड़ रुपये की दरकार

बैंक के पुनर्गठित निदेशक मंडल की बैठक आज होगी

अभिजित लेले
मुंबई, 25 मार्च

संकटग्रस्त निजी क्षेत्र के येस बैंक को अगले एक-दो साल में नियामकीय नियमों के मुताबिक पूंजी का स्तर बनाए रखने के लिए 13,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी की दरकार होगी।

इस बीच, बैंक के पुनर्गठित निदेशक मंडली पहली बैठक 26 मार्च को होगी। नए गैर-कार्यकारी चेयरमैन सुनील मेहता की अध्यक्षता वाला निदेशक मंडल संस्थागत निवेशकों को शेयर या परिवर्तनीय बॉन्ड व वॉरंट जारी कर पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। शेयरों को राइट्स आधार पर जारी करने का विकल्प खुला रखा गया है।

बैंक का शेयर आज बीएसई पर 15.26 फीसदी की गिरावट के साथ 29.7 रुपये पर बंद हुआ।

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक बयान में कहा कि उसने बैंक के बेसल-3 टियर-2 बॉन्ड की रेटिंग डी से बढ़ाकर बीबी कर दी है और उसे रेटिंग निगरानी में रख दिया है।

प्रबंधन ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में एनपीए में पांच फीसदी नया कर्ज जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उच्च क्रेडिट प्रावधान करना होगा। मानक कर्ज से एनपीए में जाने वाली रकम करीब 8,500 करोड़ रुपये रह सकती है।

इक्रा के अनुमान के मुताबिक, येस बैंक को नियामकीय पूंजी अनिवार्यता पूरी करने के लिए 9,000-13,000 करोड़ रुपये की इक्विटी की दरकार होगी, जिसमें कैपिटल कंजरवेशन बफर्स शामिल है। नियामकीय नियमों के मुताबिक, बैंकों को 31 मार्च 2020 तक 2.5 फीसदी कैपिटल कंजरवेशन बफर्स बनाए रखना जरूरी है।

इक्रा ने कहा कि दूसरे दौर में पूंजी जुटाने की मात्रा और समय पूंजी अनुपात भविष्य में नियामकीय स्तर से ऊपर बनाए रखने के लिहाज से अहम है।

बैंक का शेयर आज बीएसई पर 15.26 फीसदी की गिरावट के साथ 29.7 रुपये पर बंद हुआ

निजी बैंक ने संके त दिया है कि वह नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नई इक्विटी जुटाएगा।

इक्रा ने कहा कि उसे नई शेयरदारिता और बैंक के बोर्ड के पुनर्गठन से सहजता मिली है। एसबीआई व अन्य देसी बैंकों की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इससे टियर-1 पूंजी अनुपात नियामकीय स्तर से ऊपर ले जाने में मदद मिली है।

इक्विटी लगाए जाने और एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डाले जाने से बैंक का पूंजी अनुपात सुधरने की संभावना है और सीईटी-1 और टियर-1 क्रमश: 7.6 फीसदी और 7.8 फीसदी होगा। साथ ही पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 फीसदी से ज्यादा होगा।

इसके अतिरिक्त 18 मार्च को पाबंदी हटाए जाने के बाद बैंक जमाओं की निकासी का सामना कर सकता है, जिसके बाद जरूरत पड़ी तो नकदी सहायता देसी वित्तीय संस्थान और आरबीआई करेंगे।

कर्मचारियों का मार्च का वेतन काटेगी विमानन फर्म गोएयर

इंडिगो और एयर इंडिया के बाद अपने कर्मचारियों की वेतन कटौती की घोषणा करने वाली गोएयर तीसरी एयरलाइन है

अनीश फडणीस
मुंबई, 25 मार्च

देश में सभी घरेलू उड़ानें बंद किए जाने के बाद गोएयर मार्च महीने के लिए अपने सभी कर्मचारियों का वेतन काटेगी।

कोविड-19 संकट की वजह से इंडिगो और एयर इंडिया के बाद अपने कर्मचारियों की वेतन कटौती की घोषणा करने वाली गोएयर तीसरी एयरलाइन है।

एयरलाइन के मुख्य कार्याधिकारी विनय दुबे ने आज भेजे एक ईमेल में कहा, 'मौजूदा हालात की वजह से हमें मार्च महीने के लिए अपने सभी कर्मियों का वेतन काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कम नुकसान हो।' इस ईमेल संदेश में यह खुलासा नहीं किया गया है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए कितनी वेतन कटौती की जाएगी।

वेतन कटौती की समस्या ऐसे समय में सामने आई है जब घरेलू एयरलाइनें अगले तीन महीने तक अपने स्टाफ का 50 प्रतिशत वेतन देने के लिए सरकार से तुरंत पूंजी की मांग कर रही हैं। घरेलू उड़ानें 24 मार्च की आधी रात से बंद कर दी गई थीं और यह बंदी 14 अप्रैल तक बरकरार रहेगी।

वाडिया समूह की इस एयरलाइन ने अपने स्टाफ के एक वर्ग के लिए लीव विदाउट पे (बगैर भुगतान अवकाश) पर भेजने का निर्णय लिया था और विदेशी पायलटों को लागत कटौती के प्रयास के तहत निकाल दिया था था। बाद में एक महीने के लीव विदाउट पे का विकल्प ट्रेनिंग से गुजर रहे या सक्रिय तौर पर ड्यूटी से दूर रहने वाले भारतीय पायलटों के लिए लागू कर दिया गया था।

दुबे ने कहा, 'गोएयर के 14 साल के इतिहास में हमने कर्मचारियों के वेतन में कटौती या इसमें विलंब की समस्या कभी नहीं देखी थी। जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो गोएयर आप सभी के द्वारा दिए गए बलिदान (वेतन कटौती या छंटनी) की भरपाई का रास्ता खोजेगी। गोएयर के मजबूत व्यावसायिक आधार को देखते हुए, मेरा मानना है कि वह समय ज्यादा दूर नहीं है।'

एक कर्मचारी ने कहा, 'जब हमने 24 दिन तक काम किया है तो एयरलाइन मार्च का वेतन कैसे काट सकती है।' हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि नकदी बचाए रखने के लिए मौजूदा हालात में वेतन कटौती समझदारी है।

लॉकडाउन पर ब्रोकरेज की राय एक जैसी

पुनीत वाधवा

देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर अधिकतर ब्रोकरेज फर्मों की राय एक जैसी है। उनका कहना है कि लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह कड़वी गोली आवश्यक है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इसके लिए प्रोत साहन उपायों की भी जरूरत है। इस मुद्दे पर प्रमुख ब्रोकरेज की राय इस प्रकार हैं

एडलवाइस

यह मानव, अर्थव्यवस्था और वित्तीय (एचईएफ) लिहाज से एक बड़ा संकट है। वैश्विक वित्तीय संकट के मुकाबले एचईएफ कहीं अधिक गंभीर है। बाजार में 30 फीसदी से अधिक की गिरावट एचईएफ अनिश्चितता को दर्शाती है। आर्थिक अव्यवस्था, कमाई की सीमा और फंडामेंटल्स में कहीं अधिक उलटफेर होगा। उथल-पुथल अभी बरकरार रहेगा।

जेएम फाइनैंशियल

नोटबंदी के प्रयोग से सबक लेते हुए लॉकडाउन को संभवत: आर्थिक पैकेज और मौद्रिक नीति से समर्थित होना चाहिए ताकि इस उथल-पुथल से सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके। ध्यान देने की बात यह है कि शेयर बाजार के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है- राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति अथवा थोड़ी राहत देने वाली नीतियां।

मोतीलाल ओसवाल

प्रधानमंत्री ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए तीन सप्ताह के लॉकडाउन की अभूतपूर्व घोषणा की है। इस संकट की प्रकृति और उसके रोकथाम के उपायों को देखते हुए वित्त वर्ष 2021 के लिए कॉरपोरेट आय का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो गया है क्योंकि उसमें उसमें गिरावट का काफी जोखिम दिख रहा है। इसलिए प्रचलित मूल्यांकन पैमानों पर गौर करना समझदारी होगा। निफ्टी छह साल में सबसे कम 14.7 गुना रिटर्न दिया है जबकि प्रचलित मूल्य/बुक वैल्यू 1.9 गुना पर सबसे कम जीएफसी है। बाजार पूंजीकरण बनाम जीडीपी अनुपात 49 फीसदी पर है जो जीएफसी के बाद सबसे कम है।

एमके

रविवार को लॉकडाउन की तैयारी का शुरुआती चरण था और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंध के कारण तैयारी के लिए काफी समय मिला। इससे 21-दिन के लॉकडाउन की प्रभावशीलता की संभावना बढ़ जाती है। बाजार के नजरिए से हमारा मानना है कि भारत में इस बीमारी का वास्तविक प्रसार कम रहेगा।

कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज

देश भर में 21 दिनों के लिए एक पूरी तरह लॉकडाउन (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) को लागू करने का निर्णय कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने में मदद कर सकता है। हमें उम्मीद है कि सरकार और आरबीआई अपरिहार्य आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए आवश्यक वित्तीय और मौद्रिक सहायता प्रदान करेंगे। हमारा मानना है कि हालिया साहसिक राजनीतिक और सामाजिक उपायों को आर्थिक रूप से समर्थन करना चाहिए।

जियोजित फाइनैंशियल

देश में 21 दिन के लॉकडाउन को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। अर्थव्यवस्था को अस्थायी तौर पर बड़ा झटका लगेगा लेकिन यदि हम इससे सफलतापूर्वक बाहर निकलते हैं तो तो रिकवरी तेज हो सकती है। संकट की घड़ी में हमारे पास सीमित विकल्प मौजूद है।

शेयर बाजार फिर हुआ गुलजार

पृष्ठ-1 का शेष

अमेरिका ने अपनी ओर से बड़े पैकेज का ऐलान किया है और अधिकांश यूरोपीय देशों ने भी प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है।'शुरुआती कारोबार में सूचकांकों में गिरावट देखी गई थी लेकिन एशियाई बाजारों में तेजी के साथ घरेलू बाजार में भी उछाल आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जैसी कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन से बाजार का सहारा मिला। कई शेयरों में निचले स्तर पर थोक सौदे देखे गए। सेंसेक्स में चार शेयरों को छोड़कर सभी बढ़त पर बंद हुए। फेसबुक द्वारा रिलायंस जियो में 10 फीसदी हिस्सेदारी लेने की योजना से रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा 14.6 फीसदी की तेजी आई। हालांकि इस तरह की तेजी हर शेयरों में नहीं दिखी। 7000 से ज्यादा शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर को छू गए और 373 शेयरों में लोअर सर्किट लगा। बीएसई के सभी क्षेत्रों के सूचकांक बढ़त पर बंद हुए। ऊर्जा में 10.2 फीसदी और वित्तीय सूचकांक में 8.7 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों ने 1,900 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, वहीं घरेलू निवेशकों ने करीब 740 करोड़ रुपये की लिवाली की।आज की तेजी के बावजूद इस महीने बेंचमार्क सूचकांक 25 फीसदी नुकसान में है। बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार अभी यह कहना कठिन है कि बाजार ने अपना निचला स्तर पा लिया है।

बीएस बातचीत

कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी आधारित जांच किट बना रहे हैं

कोविड-19 वैश्विक महामारी फैलने के मद्देनजर सरकार ने इस वायरस का पता लगाने के लिए भारत में पीसीआर-आधारित किट के विनिर्माण की मंजूरी दी है। एंटीबॉडी-आधारित परीक्षण जैसे कई अन्य तरीके भी हैं, जो बड़े पैमाने पर तेजी से जांच के लिए उपयुक्त हैं। बायोकॉन की सीएमडी **किरण मजूमदार शॉ** ने **समरीन अहमद** से बातचीत में कहा कि कंपनी की अनुसंधान शाखा सिनजीं ऐसे किट विकसित करने के लिए काम कर रही है। शॉ कोविड-19 को नियंत्रित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कोविड-19 डेटाबेस तैयार करने और भविष्य में संचारी रोगों से निपटने की तैयारी के लिए आरऐंडडी पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पेश हैं मुख्य अंश...

सरकार ने कोरोनावायरस की जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। क्या इसके लिए निर्धारित 4,500 रुपये की कीमत उचित है?
यह बिल्कुल उचित है क्योंकि यह यह मूल्य आयातित किट की लागत के आधार पर निर्धारित की गई है।

मौजूदा परिस्थिति में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए?
हमें अभी काफी लोगों की जांच करने की आवश्यकता है, इसलिए निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी देना काफी महत्वपूर्ण कदम है। अब उन्हें निजी अस्पतालों को इसके लिए मंजूरी देने की आवश्यकता है क्योंकि हमें अस्पताल बिस्तरों की बेहद आवश्यकता है। जाहिर तौर पर सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध नहीं हैं। हमें बड़ी तादाद में चिकित्सा पेशेवरों की आवश्यकता होगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना सरकार क्षमता का विस्तार करने में समर्थ नहीं होगी।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम में भारतीय उद्योग जगत क्या भूमिका निभा सकता है?
हमें टीके के बिना इसके प्रसार को रोकना होगा। हरेक कंपनी कम से कम इतना तो कर सकती है कि वह अपने कार्यालय अथवा फैक्टरी जाने वाले कर्मचारियों को पूरी तरह से कम कर दें। जो लोग इसे बंद कर सकते हैं उन्हें दो सप्ताह के लिए ऐसा अवश्य करना चाहिए। बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कंपनियां वित्तीय योगदान कर सकती हैं। सीएसआर के तहत उन्हें जांच, वेंटिलेटर की खरीद और बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए रकम देनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत को सहयोग करने की आवश्यकता है। जब तक हमें उपचार नहीं मिलेगा तब तक इस महामारी से निपटना मुश्किल होगा। इसलिए इसे नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका एक बड़े पैमाने पर लॉकडाउन है, जैसा सरकार ने किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को घर से काम करने के लिए कहा जाना चाहिए।

कोविड-19 के लिए बायोकॉन त्वरित जांच निदान पर काम कर रही है। यह क्या है?
इस वायरस का पता लगाने के लिए कई तरह की जांच विकसित की जा सकती है। भारतीय प्रयोगशालाओं ने रियल-टाइम पीसीआर किट तैयार करने की दिशा में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी प्रयोगशाला और कोसारा जैसी कंपनी हर सप्ताह सैकड़ों-हजारों किट का निर्माण कर सकती हैं। हमें उम्मीद है कि उस किट के जरिये जांच में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ऐसा ही एक किट एंटीबॉडी आधारित किट है, जो तेजी से जांच करने में मदद कर रहा है। यह किट तीन बातें तुरंत बता सकता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं, क्या आप संक्रमित हैं और ठीक हो रहे हैं और क्या आप ठीक हो गए हैं। ये किट पीसीआर जांच से भी अधिक सटीक हैं क्योंकि सुधार के चरण को भी इंगित करते हैं। हम एंटीबॉडी-आधारित इस जांच को विकसित करने के लिए सिनजेन के जरिये प्रयास कर रहे हैं।

कोविड-19 रोगियों का डेटाबेस तैयार करना आगे कितना महत्वपूर्ण साबित होगा?
हमें कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से सीखने और स्वस्थ होने का विश्लेषण करने के लिए आंकड़ों की जरूरत है कि किसने कैसा प्रदर्शन किया। महामारी संबंधी डेटा एक वैश्विक महामारी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि बीमारी कैसे फैलती है, क्यों फैलती है, जीवित, खराब स्वच्छता, खराब स्वास्थ्य या बुढ़ापे जैसी परिस्थितियों में क्या करना था। इन सब का विश्लेषण करने की जरूरत है। अगर हमारे पास ऐसा डेटाबेस नहीं होगा तो हमें केवल आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

कोविड-19 के बाद का विश्व कैसा होगा?
मुझे उम्मीद है कि हम एक साफ-सुथरे देश के रूप में काम करेंगे और घर से काम करने के मॉडल के बारे में अधिक गंभीरता से सोचेंगे। मैं यह भी उम्मीद करती हूं कि कोविड-19 के बाद नियमित तौर पर हाथ धोना एक आवश्यकता बन जाएगा।

घरेलू वृद्धि से फार्मा शेयरों को मिल सकती है रफ्तार

ब्रोकरों को पिछले चार साल के कमजोर प्रदर्शन की भरपाई कैलेंडर वर्ष 2020 में होने की संभावना है

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 25 मार्च

सेक्टर सूचकांकों में फार्मा सेक्टर सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में शामिल है। वर्ष 2010-2015 के शानदार प्रदर्शन वाली छह वर्षों की अवधि के बाद सुरक्षित एवं रक्षात्मक दांव समझे जाने वाले फार्मा क्षेत्र ने तब से प्रमुख सूचकांकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, कैलेंडर वर्ष 2019 में जहां प्रमुख सूचकांकों ने 12 प्रतिशत का प्रतिफल दिया, वहीं इस क्षेत्र के प्रतिफल में 3 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि वर्ष 2020 की शुरुआत से हालात इस क्षेत्र के लिए सुधरने शुरू हो गए हैं। घरेलू बिक्री वृद्धि में सुधार, प्रमुख विकसित बाजारों में राजस्व में मजबूती, रुपये में गिरावट और आकर्षक मूल्यांकन से यह क्षेत्र अपने प्रतिस्पर्धियों को मात दे सकता है। कुछ तेजी का असर बीएसई हेल्थकेयर सूचकांक में दिखा है, जिसमें मार्च के शुरू से लेकर अब तक 19 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है जबकि निफ्टी में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है।

सीएलएसए के विश्लेषकों का मानना है कि इस क्षेत्र की आय मंदी की आशंका वाले बाजार में अपेक्षाकृत सुरक्षित है। दरअसल, यह ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जिसमें ब्रोकर आगामी वर्ष के लिए अपने आय अनुमान बढ़ा रहे हैं, भले ही अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में आय अनुमानों में कटौती की जा रही है।

इस क्षेत्र के लिए प्रमुख कारक घरेलू बाजार में वृद्धि की स्पष्ट संभावनाएं हैं। यह बाजार मूल्य निर्धारण में सुधार के साथ साथ मजबूत बिक्री की मदद से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। वृद्धि को 'एक्यूट' के साथ साथ 'क्रॉनिक' सेगमेंटों से भी मदद मिली है। सीएलएसए का मानना है कि बाजार में दवाओं की बढ़ती पहुंच, किफायत और मधुमेह, कार्डियक और ऑनकोलोजी थेरेपीज जैसी गंभीर अनियमितताओं के मामलों में वृद्धि समेत उद्योग के विभिन्न मजबूत विकास वाहक हैं। दो महीने तक एक अंक की वृद्धि के बाद इस क्षेत्र ने कीमत बढ़ोतरी की मदद से 12 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। विश्लेषकों को मौजूदा दो अंक की वृद्धि दर बरकरार रहने की संभावना है, जिससे भारतीय दवा कंपनियों के राजस्व के साथ-साथ उनके घरेलू परिचालन मुनाफा मार्जिन को भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। जहां बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां अपना लगभग पूरा राजस्व भारतीय बाजार से प्राप्त करती हैं, वहीं सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला और कैडिला की 40 प्रतिशत बिक्री और 50 प्रतिशत से ज्यादा आय घरेलू परिचालन से ही हासिल होती है।

विश्लेषकों को अमेरिकी बाजार में अगली कुछ तिमाहियों में मजबूत मुनाफे की संभावना है। ऐंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के कुणाल रनडीरिया अमेरिकी बाजार को लेकर सकारात्मक हैं, क्योंकि दवाओं की किल्लत पांच साल के सर्वाधिक स्तर के आसपास पहुंच गई है। उनका कहना है कि भारत कोविड-19 के कम खतरे की वजह से अपेक्षाकृत बेहतर स्थित में है। इससे कंपनियों को अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के बाजारों में अन्य देशों में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ज्यादा आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। उनका यह भी कहना है कि यदि सख्ती और चेतावनी पत्रों की वजह से कुछ संयंत्रों से किल्लत बढ़ती है तो कुछ खास उत्पादों के लिए छूट दी जा सकती है।

ग्रामीण बैंकों को मिलेगा धन

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 25 मार्च

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने आज कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में 1,340 करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने की योजना को मंजूरी दे दी। इसका मकसद ग्रामीण बैंकों की पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) बढ़ाना है, जिसे 2020-21 के दौरान 9 प्रतिशत रखे जाने की जरूरत है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार 670 करोड़ रुपये देगी और इनके प्रवर्तक बैंक भी इतनी ही राशि मुहैया कराएंगे। एक तरह से यह पुनर्पूंजीकरण योजना का हिस्सा है, जो चालू वित्त वर्ष में खत्म हो रही है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार की ओर से राशि तभी जारी की जाएगी, जब यह सूचना मिल जाएगी कि ग्रामीण बैंकों के प्रवर्तक बैंकों ने उतनी ही राशि जारी कर दी है।

पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए मार्च 2008 से प्रभावी रिजर्व बैंक की ओर से डिस्क्लोजर मानक पेश करने के फैसले के बाद एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष केंद्रीय बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती हैं। समिति की सिफारिशों के बाद मंत्रिमंडल ने 2011 में आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत 40 ग्रामीण बैंकों को 2,200 करोड़ रुपये का समर्थन दिया जाना है, जिसमें 700 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि में रखा जाना था, जिससे कमजोर आरआरबी की जरूरतों को पूरा किया जाए, खासकर जो पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

जावडेकर को भी आज नहीं मिल पाए अखबार

तमाम लोगों की ही तरह बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर को भी घर पर अखबार नहीं मिले, क्योंकि यह अफवाह फैल गई है कि अखबार छूने से कोरोना फैल रहा है। जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा, 'मुझे भी आज घर पर अखबार नहीं मिले। मैंने वेंडर से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? इस तरह की अफवाहें हैं कि समाचार पत्र छूने के बाद कोरोना वायरस फैल रहा है।' उन्होंने कहा कि कुछ हाउसिंग सोसाइटी अखबार बांटने वालों को घुसने नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा, 'यह गलत है' क्योंकि हमें अखबारों से ही सूचनाएं मिलती हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने 22 की शाम मेडिकल कर्मियों व पत्रकार दोनों के लिए तालियां बजाई थीं। *बीएस*

शुल्क प्रोत्साहन की अवधि बढ़ी

निर्यात के लिए परिधान और चादर, कालीन जैसे मेड अप उत्पादों की खेप पर केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों और शुल्कों का बोझ खत्म करने की योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। परिधान और मेड अप की निर्यात खेप पर राज्य एवं केंद्र स्तरीय कर व शुल्कों की वापसी की यह योजना अब पहली अप्रैल से तब तक जारी रहेगी जब तक कि इसे निर्यात वस्तुओं पर कर और शुल्क वापसी की नई योजना में समाहित न कर दिया जाए।

लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली में पसरा सन्नाटा

फोटोः संजय शर्मा

21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के पहले दिन दिल्ली के तमाम भीड़भाड़ इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार रहने वाले इंडिया गेट, राजपथ, राष्ट्रपति भवन सहित विभिन्न पुलों पर इक्का दुक्का वाहन नजर आए। इस दौरान सुनसान पड़े दिल्ली के प्रमुख बाजार कनॉट प्लेस का एक दृश्य

उद्योगों को सरकार से और राहत की आस

नम्रता आचार्य और ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 25 मार्च

सरकार ने आईबीसी (दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता) के तहत दिवाला की सीमा भले ही 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी है, अभी वित्तीय संस्थानों खासकर बैंकों को सरकार से और ज्यादा उम्मीद है। खासकर बैंक चाहते हैं कि एनपीए (गैर निष्पादित संपत्ति) के वर्गीकरण के लिए कम से कम 90 दिन का वक्त दिया जाए। उनका कहना है कि संकट का असली असर अगली दो तिमाहियों में नजर आएगा।

भारतीय स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'वास्तविक अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। अगली दो तिमाहियों या उससे ज्यादा वक्त तक बैंक एनपीए के स्थगन की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही उड्डयन, एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों को कुछ प्रोत्साहन देने की जरूरत है।'

अगर किसी खाते की चूक 90 दिन से ज्यादा होती है तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मौजूदा संकट में अगली दो तिमाही के दौरान बड़ी संख्या में खाते इस श्रेणी में आ जाएंगे।

सरकारी क्षेत्र के बैंक के एक वरिष्ठ बैंकर के मुताबिक अगले 3 महीने तक एक सिरे से खातों को भूल जाने की जरूरत है, जो एनपीए में तब्दील होंगे। उन्होंने कहा, 'अन्यथा बड़ी संख्या में खाते एनपीए में बदल जाएंगे।'

एक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रमुख ने कहा, 'अभी सरकार ने अनुपालन से जुड़े मसले पर राहत दी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ा राहत लेकर आएगी।'

बैंक जहां राहत की मांग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पैसे के लिए बैंकों से भुगतान के लिए वक्त की राहत की उम्मीद कर रही हैं। उदाहरण के लिए एनबीएफसी-एमएफआई का परिचालन लंबित है और एमएफआई अपने उधारी लेने वालों से धन नहीं एकत्र कर पा रही हैं। एमएफआईएन (माइक्रोफाइनैंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क) के चेयरमैन मनोज नांबियार के मुताबिक अगर एमएफआई अपने उधारी लेने वालों को कोई भी राहत देती हैं तो वह बैंकों से भी उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद करती हैं।

श्रेय के वाइस चेयरमैन सुनील कनौरिया ने कहा, 'अर्थव्यवस्था को वैश्विक महामारी से सुरक्षित करने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है। वितत्त मंत्री का फैसला स्वागत योग्य है और इससे बड़े पैमाने पर एमएसएमई को परिसमापन जैसी स्थिति से राहत मिलेगी। बहरहाल एसएमई और एमएसएमई बड़े पैमाने पर अपनी उत्तरजीविता और वृद्धि के लिए बड़े संस्थानों पर निर्भर हैं। ऐसे में सरकार को बड़े कॉर्पोरेशन को मदद करना जरूरी है, क्योंकि एमएसएमई में बड़े पैमाने पर लोग रोजगार पाते हैं और उन पर निर्भर हैं। सरकार की पर्याप्त सहायता के बगैर भारत आर्थिक तबाही की ओर चला जाएगा।' उल्लेखनीय है कि मौजूदा और अगली तिमाही में कोरोनावायरस की वजह से पुनर्गठन की स्थिति आ सकती है, आईसीए (इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट) के तहत उच्च प्रावधानों के कारण समाधान संभव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बैंकों की चिंता आगे और बढ़ेगी।

इंडसलॉ में पार्टनर सौरभ कुमार ने कहा, 'अनिश्चितता का दौर है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में कुछ नए एनपीए बढ़ेंगे। आईबीसी की धारा 7 को लंबित किए जाने और सीमा बढ़ाने से बैंकिंग सेक्टर चूक होने की स्थिति में आईबीसी के बाहर के विकल्प तलाश सकता है। सुरक्षित कर्जदाता सरफेसी की संभावना तलाश सकते हैं। बैंकों को सरकार की ओर से कुछ वित्तीय मदद की भी जरूरत पड़ सकती है।'

दिवाला की सीमा बढ़ाने से नहीं मिलेगी पूरी राहत

- बैंक चाहते हैं कि एनपीए के वर्गीकरण के लिए कम से कम 90 दिन का वक्त और दिया जाए
- बैंकों के मुताबिक संकट का असली असर अगली दो तिमाहियों में नजर आएगा
- उड्डयन, एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की जरूरत
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी बैंकों से भुगतान के लिए वक्त की राहत की उम्मीद कर रही हैं

कंपनियों को नए कर्ज की पेशकश

अनूप रॉय और जश कृपलानी
मुंबई, 25 मार्च

भारतीय स्टेट बैंक के साथ बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ बड़ौदा ने संकट में फंसी कंपनियों को नए कर्ज की पेशकश की है। वित्त वर्ष समाप्त होने वाला है और बैंक उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम छोटी और मझोली कंपनियां चूक कर सकती हैं। यूनियन बैंक और इंडियन बैंक ने भी कार्यशील पूंजी की सीमा बढ़ाने के लिए इसी तरह के कदम की घोषणा की है।

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के वर्गीकरण में 90 दिन के बाद आगे 3 महीने तक की और देरी किए जाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। अगर किसी कर्ज का भुगतान 90 दिन तक नहीं किया जाता है तो वह बैंकों के लिए खराब कर्ज बन जाता है और उसके लिए प्रावधान किए गए हैं।

कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन से बने दबाव को कम करने के लिए कॉर्पोरेट्स ने बैंकों और सरकार से कहा है कि 6 महीने के लिए नकदी की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे अपने आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को भुगतान कर सकें।

शिशिर बजाज के नेतृत्व वाले बजाज समूह के समूह वित्त निदेशक प्रबल बनर्जी के मुताबिक बॉन्ड और कर्ज की चूक दोनों ही तेजी से बढ़ेंगे, अगर रिजर्व बैंक मूलधन के भुगतान के लिए 2 साल की छूट और ब्याज के भुगतान के लिए 6 महीने से लेकर साल भर की छूट नहीं देता है। बनर्जी ने कहा, 'मंदी का बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा।' बैंकर इसे जरूरी कदम के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि इससे नैतिक आपदा होने को लेकर भी चिंता है।

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

रेटिंग एजेंसियों का भी एक खास रुख है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति कमजोर स्थिति में हो रही है और छोटे व मझोले आकार की कंपनियां बड़े पैमाने पर चूक कर रही हैं। ऐसे में रेटिंग एजेंसियां उन्हें डिफॉल्ट की श्रेणी में डाल रही हैं। रेटिंग एजेंसियां एक दिन, एक रुपये के सिद्धांत से निर्देशित होती हैं, जब वे डिफॉल्ट के बारे में फैसला करती हैं। और एक बार चूक की श्रेणी में आ जाने पर डिफॉल्ट रेटिंग कम से कम 6 महीने तक नहीं हट सकता है।

एक रेटिंग एजेंसी के अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'अब मसला यह है कि नकदी का प्रवाह सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है और बैंकों को निश्चित रूप से कंपनियों को कर्ज देना चाहिए, जिससे कि उनका नकदी का प्रवाह बना रहे और कम से कम वे अपने कर्मचारियों को वेतन देना जारी रख सकें। अगर लोगों को वेतन नहीं मिलता है तो यह अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार होगी।'

रेटिंग एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि इस मसले पर भारतीय रिजर्व बैंक और पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से कोई पत्रव्यवहार नहीं हुआ है।

अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही कुछ कंपनियां म्युचुअल फंडों (एमएफ) में लगाए अपने लिक्विड फंड को निकाल रही हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स की ओर से लिक्विड फंडों पर बड़ा दबाव है। उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक डेट एमएफ योजनाओं में से पिछले सप्ताह के अंत में 1 लाख करोड़ रुपये निवेश खींचा गया है।

एक फंड मैनेजर ने कहा, 'लॉकडाउन की वजह से रोजाना का परिचालन प्रभावित हुआ है। ऐसे में कॉर्पोरेट्स को बैंकों से वित्तपोषण में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वे कार्यशील पूंजी और कर्ज की बाध्यता पूरी करने के लिए लिक्विड निवेशों को निकाल रहे हैं।' उद्योग के एसेट्स पर दबाव की वजह से एमएफ को भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखना पड़ा है कि वह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स व कमर्शियल पेपर्स के लिए रीपो के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए।

देश में कोरोनावायरस के मामले पहुंचे 606 तक

एजेंसियां
नई दिल्ली, 25 मार्च

देश भर में 10 लोगों की मौत के साथ बुधवार को नोवेल कोरोनावायरस के मामलें बढ़कर 606 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 553 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर हालात का आकलन करने के लिए मंत्रियों के एक समूह की बैठक भी बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जहां एक ओर सरकार निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सुनिश्चित करना का प्रयास कर रही है और एन-95 मास्क पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं ताकि चिकित्सा बिरादरी को उनके काम के दौरान मदद मिल सके, वहीं दूसरी ओर अब तक 16,000 से अधिक नमूना संग्रह केंद्रों के साथ 29 निजी लैबोरेटरी को जांच के लिए पंजीकृत किया जा चुका है। अधिकारी ने कहा कि मास्कों और निजी सुरक्षा उपकरणों में कुछ आयातित पूर्जे हैं। कुछ चीजों के आयात में रुकावट है। सरकार इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्रालय एक नियंत्रण कक्ष के माध्यम से लॉकडाउन की निगरानी कर रहा है।

टेलीमेडिसिन परामर्श पर दिशानिर्देश जारी

साई ईश्वर
मुंबई, 25 मार्च

देश में अब पंजीकृत सभी चिकित्सक दूर से इलाज की सलाह दे सकेंगे। इस बारे में आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर दिशानिर्देश जारी किए।

दूर से इलाज की सलाह देना या टेलीमेडिसिन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मरीजों को दूर से निदान व उपचार की सुविधा दी जाती है।

दिशानिर्देशों के मुताबिक एक ऑनलाइन प्रोग्राम तैयार किया जाएगा और इसके बारे में मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के माध्यम से चिकित्सकों को जानकारी दी जाएगी, जिससे वे दिशानिर्देशों के मुताबिक प्रक्रिया और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस की सीमाओं से वाकिफ हो सकें।

दिशानिर्देशों के बारे में अधिसूचना जारी होने के बाद 3 साल के भीतर सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कोर्स करने की जरूरत होगी, जिससे वे टेलीमेडिसिन के माध्यम से सलाह दे सकें। दस्तावेज में कहा गया है, 'सभी टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के लिए पंजीकृत मेडिकल चिकित्सक का पेशेवर फैसला मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है।' व्हाइट पेपर में सात चीजों का जिक्र है मसलन संदर्भ, व्यक्ति की पहचान और किसी भी टेलीमेडिसिन परामर्श की शुरुआत से पहले अनुमति आदि। ये दिशानिर्देश ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ रही है और लोग अब इंटरनेट मंच और वॉयस कॉल पर निर्भर हो रहे हैं ताकि कम गंभीर बीमारियों के लिए डॉक्टर से परामर्श लिया जा सके।

एक प्रमुख आईटी सेवा कंपनी के साथ हेल्थकेयर डोमेन सलाहकार के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर सुमंत रमन कहते हैं, 'ये दिशानिर्देश व्यापक रूप से ठीक हैं लेकिन इस पूरे कोर्स को तैयार करने में महीनों लग सकते हैं और यह कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में उपयोगी नहीं होगा।'

देश में सबसे पहले टेलीमेडिसिन सेवाएं देने वाले चुनिंदा डॉक्टरों में रमन भी शामिल हैं। वर्ष 2000 में वह वेबहेल्थसेंटर डॉट कॉम जैसी वेबसाइट के सह संस्थापक बने जो ऑनलाइन परामर्श सेवाओं, मेडिकल रिकॉर्ड के ऑनलाइन स्टोर और फैसला लेने के लिए मददगार उपकरणों की पेशकश करती है।

पिछले हफ्ते ही अमेरिका के डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने टेलीहेल्थ सेवाओं के मद्देनजर फेडरल नियमों में छूट दी थी ताकि इसे सभी मेडिकेयर यूजरों के लिए खुला रखा जाए। इस कदम का मकसद यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को क्लिनिक में जाने की जरूरत न पड़े और वे जोखिम से बचते हुए डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं।

पिछले साल रिलीज हुए मैकिंजे डिजिटल इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीमेडिसिन मॉडल में इतनी तकनीकी क्षमता है कि देश के आधे ओपीडी मरीजों को परामर्श दिया जा सकता है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है, 'टेलीमेडिसिन परीक्षण से यह अंदाजा लगा है कि सुदूर इलाकों में डॉक्टरी सलाह लेने की लागत में करीब 30 फीसदी की कमी आती है। स्वास्थ्यसेवा क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से वर्ष 2025 तक 4 से 5 अरब डॉलर तक की बचत हो सकती है।'

टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कुछ हिस्से में अच्छे डॉक्टरों की कमी का समाधान करने में अहम भूमिका निभा सकता है। नवंबर में संसद में पेश किए गए जवाब के मुताबिक देश में प्रत्येक 1,445 लोगों पर एक डॉक्टर हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर के निर्धारित नियमों से काफी कम है।

बीएस सूडोकू 3698 | परिणाम संख्या 3697

		6	3	1	4			9
		1		2	9		7	
						7	1	
	4	7	5		1	6	8	
	6	2						
	9		1	7		4		
8			2	3	6	1		

4	8	5	6	7	9	1	2	3
7	6	2	8	3	1	4	5	9
9	3	1	4	5	2	8	6	7
3	9	4	1	6	5	2	7	8
2	5	8	7	9	4	6	3	1
1	7	6	3	2	8	9	4	5
5	4	3	9	1	6	7	8	2
6	2	9	5	8	7	3	1	4
8	1	7	2	4	3	5	9	6

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★★☆

सालाना गेहूं खरीद देर से शुरू कर सकती है सरकार

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 25 मार्च

कोविड-19 संकट के कारण पूरे देश में लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार सालाना गेहूं खरीद कार्यक्रम में एक सप्ताह की देरी करने पर विचार कर रही है, जिससे किसानों व अन्य लोगों की एक जगह पर जुटान न हो सके।

साथ ही खाद्य मंत्री राम विलास पासवान के मंगलवार के एक ट्वीट के जवाब से यह संकेत मिले हैं कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से धान की खरीद में भी देरी करने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पंजाब सरकार ने खरीद में दो सप्ताह देरी करने का फैसला किया है। हरियाणा में सामान्यतया 1 अप्रैल से खरीद शुरू होती है।

हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने वाले राज्य मध्य प्रदेश में करीब सभी थोक मंडियों में देरी से गेहूं खरीद की संभावना है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मंडियां बंद हैं। सामान्य वर्षों में खरीद 1 अप्रैल के पहले से शुरू हो जाती है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कुछ बड़े राज्यों ने इच्छा जताई है कि कोविड-19 के प्रतिबंधों को देखते हुए सालाना गेहूं खरीद में देरी की जानी चाहिए और इस पर अंतिम फैसला जल्द हो सकता है।'

उन्होंने कहा कि अगर खरीद प्रक्रिया की अनुमति मिलती है तो बड़े पैमाने पर मंडियों में किसान, मजदूर और अन्य कर्मचारी पहुंचेंगे, जिससे उन्हें कोविड-19 का खतरा है। भारत की सालाना गेहूं खरीद 300 से 350 लाख टन के बीच है।

अगर खरीद में देरी होती है तो इसका मतलब यह भी है कि किसानों को मौसम के उतार चढ़ाव के बीच अपने जोखिम पर फसल रखनी होगी। मध्य प्रदेश के एक किसान नेता ने कहा, 'ऐसी स्थिति होने पर गुणवत्ता के मानकों में कुछ ढील दी जानी चाहिए।' कुछ महीने पहले के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक भारत में इस साल रिकॉर्ड 1621.1 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है।

नई रणनीति

- कोरोनावायरस के कारण कई राज्यों की देर से गेहूं खरीद शुरू करने की मांग
- सामान्यतया 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है फसलों की खरीद
- अगर खरीद में देरी होती है तो मौसम की मार से किसानों को बचाना होगा अनाज

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 29

सिर्फ बंदी विकल्प नहीं

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन (बंदी) को अनिवार्य बताते हुए इसकी सराहना की जा रही है। ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि देश में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमा है। परंतु तीन सप्ताह के लॉकडाउन को हर उस चीज का विकल्प नहीं बनाया जा सकता जो सरकार को करना चाहिए या जो उसे अब तक कर लेना चाहिए था। देश में प्रति 10 लाख लोगों में 12 की जांच की जा रही है। चीन में यह आंकड़ा प्रति 10 लाख पर 221 है और अन्य देशों ने तो प्रति 10 लाख में हजारों लोगों की भी जांच की है। देश में आम व्यवस्था/उत्पादन/आपूर्ति क्षमता (उदाहरण के लिए हमारे यहां प्रति 11,600 लोगों पर एक चिकित्सक है) की दयनीय दशा हमें काफी कुछ बताती है और गाल बजाने के मौजूदा सिलसिले को ध्वस्त करने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक हर देश को अपने जीडीपी का करीब 4-5 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। एक ऐसी सक्रिय सरकार जिसने देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने के लिए केवल चार घंटे का वक्त दिया, उसने आम बजट में स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का केवल 1.6 फीसदी हिस्सा निर्धारित किया है।

दूसरा बड़ा मसला यह है कि इस लंबे लॉकडाउन की आर्थिक कीमत क्या होगी? खासतौर पर गरीबों पर इसका अप्रत्याशित असर होगा जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अनिवार्य सेवाओं और आपूर्ति के रखरखाव में भी बहुत अधिक दिक्कत आएगी जो एक हद तक अपरिहार्य है। इन तमाम बातों के बावजूद वित्त मंत्री कुछ बुनियादी घोषणाएं तक नहीं कर पा रही हैं जो अनिवार्य हैं। मसलन बेरोजगार/असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए आय समर्थन की घोषणा, छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए नकदी प्रवाह सुनिश्चित करना वगैरह। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार 15 लाख करोड़ रुपये के पैकेज पर काम कर रही है लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह समझना मुश्किल है कि घोषणा में देर क्यों की जा रही है। इससे अनिश्चितता और तनाव बढ़ रहा है। खासतौर पर आबादी के वंचित वर्ग के लोगों के बीच। देश की श्रम शक्ति का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है और उसे आय का नुकसान होगा। कम से कम आने वाले सप्ताहों के दौरान ऐसा होना तय है। सरकार ने कहा है कि वेतन-भत्तों में कटौती नहीं की जानी चाहिए लेकिन इसका प्रवर्तन मुश्किल होगा। छोटे कारोबार जोखिम में हैं और शायद वे अपने कर्मचारियों को भुगतान करने की स्थिति में न रहें। हकीकत में छोटे कारोबारों को बचाना आवश्यक है और ऐसे में नियामकीय निगरानी से परे जाकर हस्तक्षेप करने होंगे। जो कर्मचारी दैनिक वेतन पर निर्भर हैं उन पर सबसे बुरा असर होगा क्योंकि उनके पास कोई बचत नहीं होती।

प्रमाण बताते हैं कि कई राज्य केंद्र से भी ज्यादा कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए केरल ने इस संकट से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है। उत्तर प्रदेश ने दैनिक मजदूरों के खातों में पैसे डालने की पहल की है। गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार का राज्यों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। उदाहरण के लिए देश में करीब 18 लाख बेघर लोग हैं जिन्हें आने वाले दिनों में राज्य सरकारों की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य दोनों के लिए यह सुनिश्चित करना अहम होगा कि अनिवार्य वस्तुएं और सेवाएं उन्हें मिलती रहें क्योंकि लॉकडाउन उत्पादन और आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। यदि खेतों से निकली ताजा उपज की बिक्री नहीं होती है तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आय प्रभावित होगी और आर्थिक समस्या बढ़ेगी।

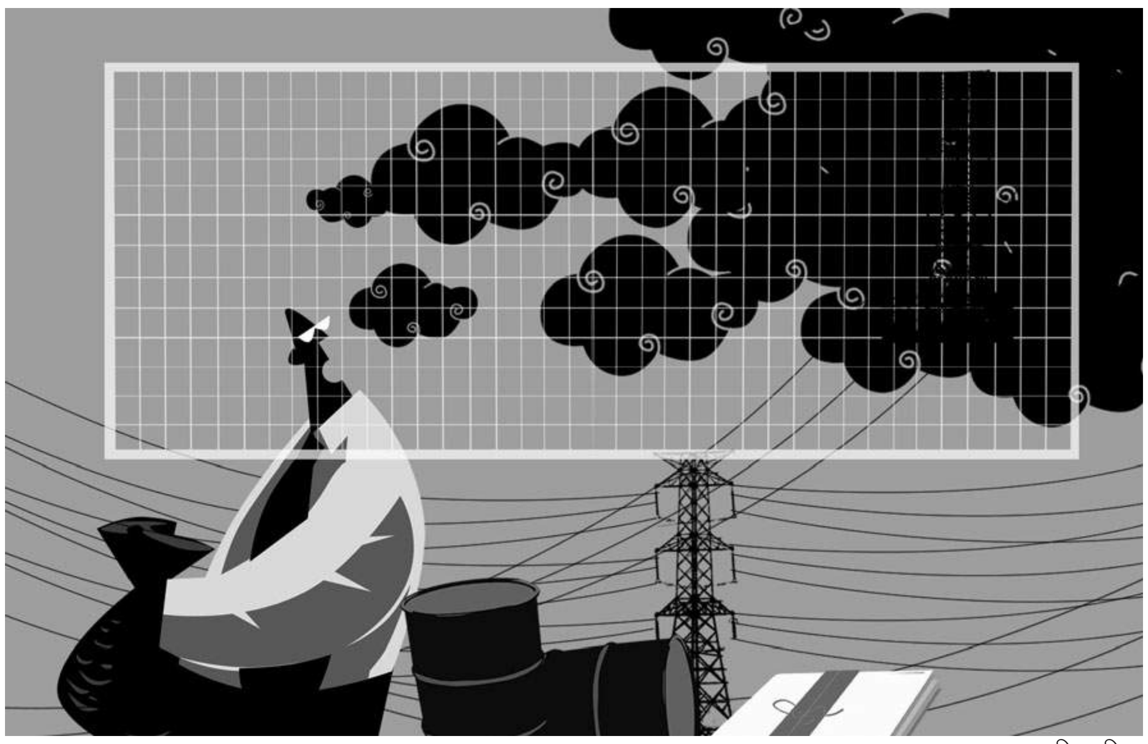

विनय सिन्हा

चौतरफा आपदा और निपटने के तरीके

पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विषयों पर एक के बाद एक संकट सामने आए हैं। ये इतने व्यापक हैं कि विभिन्न देशों और समुदायों की प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम पड़ सकती है। बता रहे हैं अरुणाभ घोष

कोविड-19 की महामारी फैलने के पहले ही चालू वर्ष अनिश्चितता के साथ शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगी आग में 1,86,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग जल चुका था। फरवरी में अंटार्कटिका का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस हो गया जो जलवायु परिवर्तन में गिरावट का स्पष्ट संकेत है। जिंस कीमतों में गिरावट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग की कमी बनी हुई है और तेल कीमतें भी काफी घट गई हैं।

अब हालात और खराब हुए हैं। कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ने के साथ ही शहर, देश और क्षेत्र तक पूरी तरह बंद कर दिए गए। रूस ने तेल उत्पादन में कटौती करने से इनकार कर दिया है। इसके कारण सऊदी अरब ने बाजार में और अधिक तेल की भरमार कर दी और कीमतें लुढ़क गईं। सीमाएं बंद होने और आपूर्ति शृंखला बाधित होने, वस्तुओं और सेवाओं के बाधित होने से लोगों की स्थिति और खराब होने की आशंका है। आर्थिक प्रभाव नजर आने लगा है। डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 11 साल से चल रही तेजी गत सप्ताह समाप्त हो गई।

यह झटकों का एक तूफान सा है। पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक संकट का ऐसा सिलसिला जो राज्यों और समुदायों की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को ही संकट में डाल सकता है। कोरोनावायरस ने आर्थिक संकट नहीं पैदा किया, बल्कि जो हालात पहले से खराब थे, इसने उनमें थोड़ा इजाफा किया। वर्ष 2008 में दुनिया का सामना वैश्विक वित्तीय संकट और खाद्य आपूर्ति संकट से एक साथ हुआ। वित्तीय संकट की वजह वित्तीय कुप्रबंधन और जोखिम के संकेतों पर ध्यान नहीं देना थी। खाद्य आपूर्ति संकट के लिए बढ़ती उर्वरक कीमत और ऊर्जा लागत, जैव ईंधन तैयार करने में अनाज का इस्तेमाल और प्रतिकूल मौसम आदि वजहें जवाबदेह थीं। प्रमुख चावल निर्यातक देशों ने निर्यात पर रोक लगा दी। खाद्य कीमतों के झटके ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कमजोर वित्तीय स्थिति वाले देशों को प्रभावित किया। अरब उभार के लिए आंशिक तौर पर यह भी एक वजह था। हम एक बार भी ऐसे ही संयुक्त संकट से गुजर रहे हैं।

जलवायु विज्ञान में वैज्ञानिक ऐसे बिंदुओं का उल्लेख करते हैं जहां जोखिम बहुत बढ़ जाता है। ये पृथ्वी के भौतिक जलवायु तंत्र में बदलाव से संबंधित हैं और हमारे पर्यावास से संबंधित हैं जिनके सीमा पार कर जाने पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का सिलसिला तेज हो सकता है और समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। विश्व मौसम संस्थान का अनुमान है कि सन 2030 तक पृथ्वी का तापमान 1.65 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

कई अन्य कारक भी समस्या में इजाफा कर सकते हैं। पानी से जुड़ा तनाव सीमा पार तनाव को जन्म दे सकता है। बेमौसम की बारिश या खराब मॉनसून कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग में कमी आ सकती है। तेल कीमतों में गिरावट भारत और चीन जैसे बड़े आयातकों के लिए अस्थायी रूप से तेजी का सबब बन सकता है। सरकारों को तय करना होगा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करना है या कम कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को देकर मांग को बढ़ाना है। इस बीच मौसम की अतिरंजना लगातार बढ़ती चली गई। सन 1990 से 2018 के बीच भारत में ऐसी करीब 300 घटनाएं घटीं। इनमें भी अधिकांश घटनाएं वर्ष 2005 के बाद की हैं। सन 1980 के बाद से बाढ़ की घटनाएं तीन गुना बढ़ गई हैं।

हम पृथ्वी के साथ क्या करते हैं यह बात बहुत मायने रखती है और पृथ्वी हमारे साथ क्या करती है। परंतु असल बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। व्यापक जन स्वास्थ्य संकट इस बात की अंतदृष्टि प्रदान करता है कि दुनिया को समय-समय पर सामने आने वाले वित्तीय संकट को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, व्यापारिक तनाव से कैसे निपटना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के संकट से कैसे निपटना चाहिए।

पहला परिदृश्य: पूरी तरह बंदी। यह सबसे खराब नतीजा है। विभिन्न देश अपने आपको आंतरिक रूप से बंद कर सुरक्षित होने की कोशिश में हैं। वायरस का प्रसार रोकने के लिए यात्राओं पर रोक आवश्यक थी। परंतु सरकार विपरीत आर्थिक प्रभावों से कैसे निपटेगी? यूरोप की सरकारों के पास अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की सीमित गुंजाइश है। अमेरिका ने कई ऐसे उपाय अपनाए हैं जिससे शेयर कीमतें कमजोर हुई हैं। चीन अर्थव्यवस्था को गति देना चाहता है लेकिन उसका निर्यात बाजार बंद है। समायोजित राजकोषीय प्रोत्साहन के अभाव में सरकारें व्यापार संरक्षण का रुख कर सकती हैं। इससे समस्या बढ़ेगी।

दूसरा परिदृश्य: आपातकालीन सेवाएं। यह समयबद्ध प्रतिक्रिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशन के अधीन संसाधनों को ऐसे क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है जहां स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हों। विभिन्न देश ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं साझा करने को तैयार हो गए हैं ताकि गलत सूचनाओं का प्रसार रोका जा सके और जनता का भरोसा मजबूत हो। यदि सन 2020 के मध्य तक वायरस अपने चरम पर पहुंचता है तो सुधार की शुरुआत हो सकती है। परंतु दक्षिण एशिया में खराब मॉनसून या अमेरिका में कोई बड़ा तूफान आर्थिक सुधार को एक और झटका दे सकता है।

तीसरा परिदृश्य: सामुदायिक कदम। जहां खतरा ज्यादा हो वहां छोटे समूहों में बेहतर सहयोग हो सकता है। स्थानीय प्रतिक्रिया में सामाजिक तौर पर जवाबदेही भरा व्यवहार शामिल है। एक बार जोखिम की सीमा का उल्लंघन हो जाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मौसम की अतिरंजना भी आशंकाओं को दोबारा जन्म देगी। भारत ने चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी देकर और लोगों का जीवन बचाकर अच्छा काम किया है। परंतु केवल सामुदायिक कदमों से आपदा के बाद की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता।

परिदृश्य 4: समेकित कदम। जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों, पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रियों की आपात बैठक के साथ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं चार प्रतिज्ञाएं कर सकती हैं: (1) सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधन की पूलिंग (2) 18 महीनों के व्यापारिक प्रतिबंध पर और प्रतिबंध (3) समन्वित वित्तीय प्रोत्साहन अपनाने होंगे और छोटे कारोबारों की मदद से व्यय शक्ति बढ़ानी होगी (4) अमीर और गरीब देशों के सर्वाधिक संवेदनशील लोगों के लिए जलवायु जोखिम मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया।

मैं एकांत में बैठकर यह लिख रहा हूं। आपात परिस्थितियां हमेशा तार्किक प्रत्युत्तर नहीं पेश करतीं। कई बार ऐसे नतीजे सामने आते हैं जो कम उपयुक्त हों। हमें व्यक्तिगत, संस्थागत और सामुदायिक स्तर पर हल तलाशने होंगे। और आशा करनी चाहिए कि हमारे नेता अंतरराष्ट्रीय सहयोग को तवज्जो देंगे।

वैमानिकी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का समुचित वक्त

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

हाल में नई दिल्ली में उद्योग जगत के लोगों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2018 की रक्षा उत्पादन नीति के कई लक्ष्यों का उल्लेख किया। उन्होंने निजी क्षेत्र से मांग की कि वह सन 2025 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन को बढ़ाकर 26 अरब डॉलर तक पहुंचाए। ऐसा करने से उस वर्ष कुल रक्षा विनिर्माण एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा जो सन 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा।

सिंह ने कहा कि सरकार का इरादा वैमानिकी उद्योग को 2024 तक 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये करने का है। इसके लिए वैश्विक वैमानिकी उद्योग को भारत से कलपुर्जे खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वैमानिकी क्षेत्र में एमएसएमई की तादाद दोगुनी करके 16,000 करने का लक्ष्य है।

फिलहाल वार्षिक वैमानिकी उत्पादन 30,000 करोड़ रुपये है। अकेले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) 20,000 करोड़ रुपये का कारोबार करती है। शेष एक तिहाई हिस्सा टाटा और महिंद्रा समूह जैसी कंपनियों के ऑफसेट उत्पादन और तमाम एमएसएमई द्वारा कलपुर्जों के निर्माण से आता है। एचएएल के उत्पादन बढ़ाने की एक सीमा है क्योंकि यह कंपनी सैन्य विमान बनाती है।

रक्षा क्षेत्र का पूंजी आवंटन एक अंक में बढ़ रहा है ऐसे में आश्चर्य नहीं कि एचएएल का टर्नओवर भी 2018-19 में 7.8 फीसदी की दर से और इस वर्ष महज 4 फीसदी की दर से बढ़ा। कंपनी के लिए नकदी का इंतजाम करने वाले सुखोई-30एमकेआई का उत्पादन अगले वर्ष 222 विमान तैयार होने के साथ बंद हो जाएगा। सुखोई-30 के बाद 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलना था लेकिन सरकार ने 36 राफेल विमान खरीद लिए जो पूरी तरह फ्रांस में बनेंगे। वायुसेना द्वारा 114 मझोले लड़ाकू विमान खरीदने या नौसेना द्वारा 57 कैरियर डेक आधारित लड़ाकू विमान खरीदने की भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। हाल में शामिल विमान मसलन सी-130 सुपर हर्क्यूलिस और सी-17 ट्रांसपोर्टर, बोइंग पी-81 पोसेडियन समुद्री विमान, अपाचे, चिनूक और एमएच-60आर हेलीकॉप्टर आदि अमेरिका से तैयार स्थिति में खरीदे गए। एचएएल तेजस फाइटर और रूसी कामोव-226टी, स्वदेशी ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर के निर्माण से राहत पा सकता है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में एचएएल को विकास के लिए जबरदस्त समर्थन की जरूरत होगी।

ऐसे में 60,000 करोड़ रुपये के वैमानिकी उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में एमएसएमई मददगार हो सकती हैं जो वैश्विक आपूर्ति शृंखला के लिए उत्पादन कर रही हैं। सरकार को इनकी पूरी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले, उसे यह मानना चाहिए कि वैश्विक ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हमारी कंपनियों का मुकाबला ऐसे प्रतिस्पर्धियों से है जिन्हें उनकी सरकारें कर और निर्यात प्रोत्साहन के रूप में काफी समर्थन देती हैं। हमारी सरकार को भी अपनी विमानन कंपनियों को बेहतर कारोबारी माहौल मुहैया कराना चाहिए। हमारी कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की लागत और फंड तक पहुंच न होना है। कई मामलों में भारतीय एमएसएमई ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का ऑर्डर इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनके पास जरूरी पूंजी नहीं थी। इससे कारोबार का नुकसान तो हुआ ही, रोजगार तैयार करने के अवसर भी हाथ से गए। सरकार को एक विशिष्ट फंड तैयार करना चाहिए ताकि एमएसएमई को शीघ्र पूंजी मुहैया कराई जा सके।

यदि सरकार वैमानिक विनिर्माण दोगुना करने को लेकर गंभीर है तो उसे एमएसएमई को विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों में शामिल करना चाहिए। विदेशी कारोबारियों को आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार इन एमएसएमई के साथ है। सरकार को वैश्विक कंपनियों को कर प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे भारतीय एमएसएमई के साथ काम करें। एमएसएमई के निर्धारण मानक बदल कर 10 करोड़ रुपये के संयंत्र और मशीनरी के बजाय इसे सालाना राजस्व से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

दूसरा, सरकार को कौशल विकास में गुणवत्ता पर जोर देना होगा। इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को औद्योगिक भागीदारी की इजाजत देनी होगी। पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को औद्योगिक आवश्यकता के अनुरूप बनाना होगा। पहले ही कई कंपनियां अपना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रही हैं। सरकार को बौद्धिक संपदा निर्माण, पेटेंट और अन्य अविष्कारों के लिए एक कानूनी बौद्धिक संपदा संरक्षण तंत्र विकसित करना होगा जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हों। वैश्विक कंपनियों को प्रोत्साहित करना होगा ताकि वे सीखने में निवेश करें।

तीसरा, कोरोनावायरस की महामारी जिस नाटकीय तेजी से फैल रही है, उसे देखते हुए एक सुरक्षित कारोबारी माहौल में ही नतीजे हासिल होंगे। जेफ बेजोस जैसे उद्योगपतियों के प्रति हाल के रवैये ने इन आशंकाओं को बढ़ाया है।

कारोबारी पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कारोबार और खुशी को साथ रखना अच्छा लगता है। आश्चर्य नहीं कि अमेरिका के सबसे रहने लायक शहरों में से एक सिएटल देश के विमानन उद्योग का गढ़ है। इसी तरह विदेशी उद्योगपति बेंगलूरु की संस्कृति के कारण आकर्षित होते हैं। ऐसे में जैसा कि सरकार कह रही है यदि उत्तर प्रदेश में अधिग्रहण एवं विकास कॉरिडोर विकसित किया गया तो उसमें विदेशी उद्यमी रुचि नहीं लेंगे। रक्षा मंत्री ने विमानन उत्पादन के लक्ष्य तय करते समय उन सीमाओं का ध्यान नहीं रखा जो राह रोकती हैं: निराशाजनक बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था की कमजोरी, खराब सामाजिक माहौल, कौशल की कमी, फंड तक कमजोर पहुंच आदि। इन चीजों को दुरुस्त करना प्राथमिक आवश्यकता है।

कानाफूसी

10 दिन, 3 मुख्य सचिव

मध्य प्रदेश में बीते 10 दिन के भीतर 3 मुख्य सचिव बने। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अपने शुरुआती आदेशों में से एक में नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह बैंस को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। सन 1985 बैच के अधिकारी बैंस को चौहान का करीबी माना जाता है। कुछ ही दिन पहले 16 मार्च को पिछली कमल नाथ सरकार ने एम गोपाल रेड्डी को इस पद पर नियुक्त किया था। रेड्डी ने एस आर मोहंती का स्थान लिया जिन्हें सरकार ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी का महानिदेशक बनाया है। यह अकादमी प्रदेश सरकार और भारत सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करती है। इस कदम के साथ ही नए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक बदलावों की शुरुआत कर दी है।

गरीबों की फिक्र

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कोरोनावायरस के प्रसार की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश और समूचे देश में किए गए लॉकडाउन को लेकर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इससे लाखों गरीब और मेहनतकश लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में भुखमरी जैसी स्थिति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को इन लोगों को तत्काल राहत मुहैया करानी चाहिए। मायावती ने बसपा के प्रभावशाली समर्थकों से कहा कि वे जरूरतमंदों की मदद करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके मोबाइल फोन कंपनियों से कहा कि वे गरीबों को नि:शुल्क या सब्सिडी आधारित सेवाएं मुहैया कराएं क्योंकि इन दिनों गरीबों की आय बुरी तरह प्रभावित हुई है।

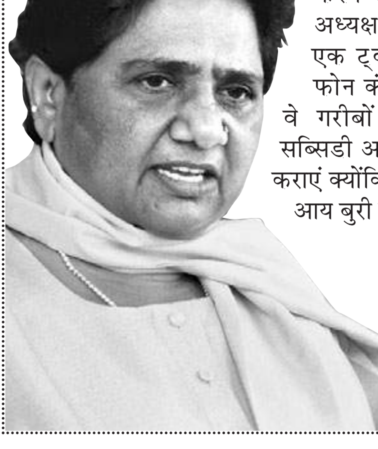

आपका पक्ष

कोरोना की मजदूरों पर दोहरी मार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन के लिए देश से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन गंभीरता से नहीं किया गया तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। हालांकि अब प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से भी निपटा जा सकता है। पुलिस सख्ती दिखा भी रही है, जबकि जनता कर्फ्यू के लिए ऐसे सख्त प्रतिबंध नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों ने जनता कर्फ्यू को हल्के में लेते हुए उसी दिन शाम पांच बजे के बाद लापरवाही बरतना शुरू कर दिया था। सरकार और प्रशासन ने इसे देश की सेहत के लिए खतरनाक समझा और सख्ती करना शुरू किया। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने इस वायरस की चिंगारी को आग का रूप धारण करने से पहले ही सख्ती दिखाई होती तो शायद देश को लॉकडाउन करने की इतने लंबे समय तक जरूरत न पड़ती। यहां सवाल यह भी है कि मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, ऑटो-रिक्शा चलाने वालों आदि के पास घर-परिवार का खर्चा चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए जिनकी कमाई बंद हो गई है। इसके लिए हर क्षेत्र के पार्षद और प्रधान को अपने-अपने क्षेत्र के मजदूरों की पहचान कर सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। कई कंपनियों ने कर्मचारी को घर से काम करने की इजाजत दी है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

21 दिन के लॉकडाउन के दौरान मेडिकल सहित सभी आपात सेवाएं खुली हैं *-पीटीआई*

धरातल पर पहुंचे लोक सेवक

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में लोक सेवकों और प्रशासकों के योगदान को रेखांकित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विकसित देशों को विकसित श्रेणी में पहुंचाने में वहां के दक्ष लोक सेवकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन विकासशील देश आज भी विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि भले ही भारत आजादी के ठीक बाद के समय की तुलना में आज बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आजादी के समय अंग्रेजों से विरासत में मिली अफसरशाही और लोक सेवा संरचना में ढेरों खामियां थीं, जिसमें से अधिकांश आज भी मौजूद है। इनमें वित्तीय भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, कमीशनखोरी प्रमुख हैं। यह देखा जाता है कि कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ स्तर के लोक सेवक केवल नाममात्र और परिचय के लिए ही लोक सेवक कहलाना पसंद करते हैं। जमीनी स्तर पर आम जन के प्रति उनका व्यवहार सामंती और मालिकों जैसा होता है। अपने वाजिब काम के लिए दफ्तर पहुंचे आम नागरिक को पूर्णत: सक्षम अधिकारी की दया और कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसे में लोक सेवक वास्तव में सेवक के स्थान पर दाता और कृपानिधान की भूमिका में दिखाई देते हैं। विभिन्न कमियों की वजह से लोक सेवा का काम धरातल पर समुचित रूप से नहीं होता दिखता है। लिहाजा जनता के जीवन स्तर को उठाने और देश के विकास को गति देते हुए विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए लोक सेवा को जमीनी स्तर पर पहुंचाना बहुत जरूरी है।

ऋषभ देव पांडेय, कोरबा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

ई-कॉमर्स पर पड़ा लॉकडाउन का असर

फ्लिपकार्ट आज फिर शुरू करेगी किराना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति। एमेजॉन उन उत्पादों की आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है, जिनकी ग्राहकों को कोविड-19 महामारी के दौरान जरूरत है

पीरजादा अबरार और नेहा अलावधी

डिलिवरी एजेंटों की पिटाई के कारण कई ई-कॉमर्स कंपनियां परिचालन बंद करने का ले रहीं फैसला

पुलिस के सख्ती से पेश आने के आरोपों के बीच फ्लिपकार्ट, एमेजॉन और बिगबास्केट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने नए ऑर्डर लेना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसे देखते हुए दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक समेत बहुत सी राज्य सरकारों ने उनके प्रतिनिधियों से संपर्क साधकर उनके डिलिवरी एजेंटों के बचाव एवं सुरक्षा का भरोसा दिया है।

इन राज्यों ने घोषणा की है कि वे पुलिस को बताएंगे कि राज्यों की सीमाओं पर ई-कॉमर्स कंपनियों का सामान ले जाने वाले वाहनों को न रोकें और उनके डिलिवरी एजेंटों के लिए कर्फ्यू पास की व्यवस्था करें ताकि वे आसानी से आवाजाही कर सकें।

फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, ग्रोफर्स और एमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियो ने बुधवार को या तो नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया या उन्होंने केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की घोषणा की है। ये कंपनियां लॉकडाउन की अवधि में परिचालन की संभावनाओं का आकलन कर रही हैं। ये कंपनियां अपने ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने के लिए स्थानीय सरकारों और पुलिस प्रशासन का सहयोग मांग रही हैं।

फ्लिपकार्ट के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने कहा, 'हम अपने डिलिवरी कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने स्थानीय सरकारों और पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा है ताकि अपने ग्राहकों की जरूरतें पूरी कर सकें क्योंकि वे लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।'

इससे पहले एमेजॉन इंडिया ने कहा था कि वह फिलहाल ऑर्डर लेना बंद कर रही है और कम प्राथमिकता के उत्पादों की डिलिवरी रोक रही है। वह उन उत्पादों की डिलिवरी को प्राथमिकता दे रही है, जिनकी ग्राहकों को कोविड-19 के दौरान सबसे अधिक जरूरत है।' एमेजॉन इंडिया के एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया, 'हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने ग्राहकों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण जरूरतें पूरी करने के लिए हम अपनी उपलब्ध फुलफिलमेंट और लॉजिस्टिक क्षमता का इस्तेमाल उन उत्पादों की आपूर्ति में कर रहे हैं, जो हमारे ग्राहकों के लिए इस समय जरूरी हैं।'

गृह मंत्रालय के 21 दिन के लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के मुताबिक खाद्य, दवा और चिकित्सा उपकरण सहित अहम वस्तुओं की डिलिवरी करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक सेवाओं का हिस्सा हैं। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इसमें सही संवाद न होने का भी मसला है। प्रशासन नए-नए परिपत्र ला रहा है, जो पिछले परिपत्रों से बिल्कुल उलट हैं। इससे जमीनी स्तर के स्थानीय अधिकारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।' अधिकारी ने कहा, 'बहुत सी ई-कॉमर्स कंपनियां परिचालन बंद करने का फैसला ले रही हैं क्योंकि प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और डिलिवरी कर्मचारियों को पीटा जा रहा है।'

केवल ई-कॉमर्स कंपनियां ही नहीं बल्कि ऑनलाइन दवा कंपनियों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में 25,000 से अधिक पिन कोड पर दवाओं की डिलिवरी करने वाली मेडलाइफ ने कहा कि उसके बहुत से डिलिवरी एजेंटों की पुलिस ने पिटाई की है। मेडलाइफ के सीईओ और सह-संस्थापक अनंत नारायण ने कहा, 'दिल्ली के टोडापुर क्षेत्र में मेडलाइफ का डिलिवरी कर्मचारी प्रकाश कर्फ्यू पास लेकर लौट रहा था। फुलफिलमेंट सेंटर लौटते समय रास्ते में पुलिस ने उसकी पिटाई की। वह घायल है और उसके चेहरे एवं शरीर पर खरोंच आई हैं। हमें बेंगलूरु में भी ऐसी ही घटनाओं की खबर मिली हैं।'

एक अग्रणी ऑनलाइन दवा डिलिवरी कंपनी नेडमेड्स ने भी अपने ग्राहकों से कहा है कि उसे ऑर्डरों की डिलिवरी में देरी हो रही है क्योंकि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद स्थानीय और क्षेत्रीय यात्रा प्रतिबंधों से कूरियर कंपनियों को अस्थायी रूप से अपना परिचालन रोकना पड़ रहा है।

इसने कहा, 'हालांकि यह देरी पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हम सभी सरकारी एजेंसियों और कूरियर कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आवश्यक दवाएं और हेल्थकेयर उत्पाद आप तक जल्द से जल्द पहुंचें।'

उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा सामान पहुंचाने के तीन प्रमुख स्तर/केंद्र हैं, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स तथा डिलिवरी। पुलिस अधिकारियों ने कई वेयरहाउसों को दुकान या भंडारगृह के अंतर्गत वर्गीकृत करके बंद करा दिया है। एक व्यक्ति ने कहा, 'सीमाएं सील हो जाने से बसें तथा ट्रकों की आवाजाही बंद है। साथ ही, अगर ये कंपनियां अपना सामान रेलवे के जरिये भी भेजना चाहें तो ट्रेन की कम आवाजाही तथा क्षमता में कमी से सामान पहुंचने में काफी समय लग जाएगा।'

सामुदायिक प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 79 प्रतिशत लोग आवश्यक वस्तुओं को समय पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही, 32 प्रतिशत लोगों को खुदरा स्टोर पर आवश्यक सामान भी नहीं मिल रहा है।

लोकल सर्किल ने कहा, 'कई ग्राहकों ले लोकर सर्किल पर बताया कि ग्रोफर्स, बिगबास्केट, एमेजॉन तथा फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स तथा ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म से उनके घर तक सामान नहीं पहुंच रहा है और अब बहुत से सामान उपलब्ध भी नहीं हैं।'

बुधवार को कई राज्यों ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के उपाय कर रहे हैं कि ई-कॉमर्स कंपिनयों द्वारा दी जा रही आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि उसके सभी अधिकारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केटप्लेस, फूड एग्रीगेटर्स तथा रिटेल दुकानों द्वारा होम डिलिवरी की अनुमति देने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की है कि राज्य 21 दिनों के बंद के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहा है। राज्य सब्जी-विक्रेताओं, ग्रॉसरी तथा ई-कॉमर्स डिलीवरी कर्मियों को आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पास उपलब्ध करा रहा है।

बेंगलूरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने ई-कॉमर्स, खाद्य, मेडिसिन फर्मों एवं किराना एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने बताया कि विभाग 'ड्यूटी पास' जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

इस बीच, फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्याधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा है कि कंपनी किराना तथा आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी फिर से शुरू कर रही है क्योंकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने आपूर्ति श्रृंखला के निर्बाध आने-जाने तथा डिलिवरी एग्जीक्यूटिव्स को सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन दिया है। कृष्णमूर्ति ने कहा, 'हम अपने कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित तथा कारगर तरीके से अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना जारी रखेंगे। हम संकट की इस घड़ी में अपने कुशल तथा मजबूत वितरण नेटवर्क का लाभ देश भर के ग्राहकों को देने के लिए तैयार हैं।'

ई-कॉमर्स को एक आवश्यक सेवा के रूप में मान्यता देने के लिए एमेजॉन इंडिया के वैश्विक वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख (भारत) अमित अग्रवाल ने बुधवार को ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 'हम इस अहम समय में नागरिकों की सेवा के लिए अपने सभी संसाधनों के साथ पूरी तरह तैयार तथा प्रतिबद्ध हैं। हम स्थानीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे हमारे साथ मिलकर काम करें और हमें मदद करें।'

मदद की गुहार

- दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक समेत कई राज्य सरकारों ने ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों को उनके डिलिवरी एजेंटों की सुरक्षा का भरोसा दिया
- कंपनियां अपने ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने के लिए स्थानीय सरकारों और पुलिस प्रशासन का मांग रही सहयोग
- गृह मंत्रालय के निर्देशों में ई-कॉमर्स को बताया गया है आवश्यक सेवाओं का हिस्सा

सरकार से मिले कैट प्रतिनिधि

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के साथ ही ई-कॉमर्स तथा रिटेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा और गृह, वाणिज्य एवं अन्य मंत्रालयों के दूसरे अधिकारियों से भी मुलाकात की और सभी प्रतिनिधियों ने उपने उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा की।

व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं की नियमित आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, निर्माता से थोक व्यापारी, थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से उपभोक्ताओं तक सामान आपूर्ति के जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे व्यापारियों की सुरक्षा तथा किसी बी तरह के संभावित उत्पीड़न को रोकने के विषयों को भी उठाया। परिवहन के साधनों का अनउपलब्धता तथा लॉजिस्टिक से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी बात की गई।

कैट ने एक बयान में कहा, 'हमने इस बातचीत में परिवहन क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का अनुरोध किया और पूरे में सामान की आपूर्ति बनाए रखने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। बातचीत में आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण भारत में निर्बाध आपूर्ति के साथ ही अन्य अहम मुद्दों पर बात की गई।' सरकार के प्रतिनिधियों ने देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का आश्वासन दिया।

लॉकडाउन से कई राज्यों की सीमाओं पर करीब 5 लाख ट्रक चालक और हेल्पर फंसे हुए हैं फोटोः पीटीआई

देश भर में राज्यों की सीमाओं पर फंसे ट्रक

शैली सेठ मोहिले

एलपीजी सिलिंडर से भरे ट्रक का 28 वर्षीय चालक मोहम्मद जावेद मंगलवार दोपहर से ही हुबली चेकपोस्ट पर फंसा हुआ है। उसके लिए वहां न भोजन है, न ही पानी की व्यवस्था। सीमा पर तैनात पुलिसकर्मी उसे सीमा पार करने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है।

जावेद उन लगभग 5 लाख चालकों और हेल्परों में शामिल है जो विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर फंसे हुए हैं। यह अनुमान इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) द्वारा व्यक्त किया गया है। सरकार द्वारा सीमाओं को सील किए जाने के सरकारी आदेश के बाद जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को भी निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

वह कहते हैं, 'मैं आज सुबह 4 बजे मंगलोर से चला था और 1 बजे से हुबली के चेक पोस्ट पर ही रुका हुआ हूं। यहां तैनात पुलिस अधिकारी मुझे आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और जब मैं उनसे जाने देने को कहता हूं तो वे मुझे पीटने लगते हैं। वे ठीक से बात करने को भी तैयार नहीं हैं। मैं यहां सिर्फ पानी के सहारे जिंदा हूं और अब वह भी समाप्त हो गया है।' उन्होंने कहा कि इस इलाके में एलपीजी सिलिंडरों से लदे कम से कम 25-30 ट्रक फंसे हुए हैं।

श्री आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंसी (जहां जावेद काम करते हैं) के पार्टनर सुरेश खोसला का कहना है कि वह तत्काल आधार पर ट्रकों की रिहाई के लिए फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के संपर्क हैं। खोसला ने बताया कि उनकी कंपनी जरूरी थोक जिंसों की आपूर्ति करती है, लेकिन उन्हें अपना व्यवसाय बरकरार रखना एक चुनौती बन गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के सभी प्रवेश मार्गों को कोरोनावायरस की वजह से बंद कर दिया गया है।

इस व्यवसाय से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सभी ढाबा और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, जिससे चालकों के लिए भूखे मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है। सामान की लदाई के वक्त तो भोजन मिल जाता है पर रास्ते में ढाबा खुले नहीं नहीं मिलते।'

सभी एंसिलियरी ऑटोमोबाइल दुकानों को बंद कर दिए जाने से वाहन की मरम्मत करना भी संभव नहीं है और किसी तरह की खराबी की स्थिति में आप वाहन को दोबारा सड़क पर नहीं ले जा सकते। चालकों और हेल्परों के पारिवारिक सदस्य भी चिंतित हैं और वे उनकी जल्द घर वापसी चाहते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के चेयरमैन बालमलकीत सिंह का मानना है कि उत्पादों की ढुलाई गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

सिंह का कहना है, 'पर्याप्त भोजन या बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं होने से ट्रक चालक घर पर ही रहना चाहते हैं।' वह कहते हैं कि ट्रकों की आवाजाही में विलंब जरूरी सामान की श्रेणी को लेकर भ्रम की वजह से भी हो रहा है। चालकों को यह पूरी जानकारी नहीं है कि क्या एसेंशियल यानी जरूरी और क्या गैर-जरूरी है।

> सभी ढाबा और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, जिससे चालकों के भूखे मरने की नौबत है

आईएफटीआरटी में वरिष्ठ फेलो एस पी सिंह कहते हैं, 'ट्रक चालकों का लदान स्थलों से बड़ी तादाद में पलायन हुआ है। वे घर लौट रहे हैं। लगभग 250,000 से 300,000 चालक पहले ही अपने पैतृक स्थान जा चुके हैं।' सिंह ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हमने सरकार से राहत पैकेज देने को कहा है। ट्रक मालिक किसी तरह की मदद करने में सक्षम नहीं हैं। चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।'

कोरोनावायरस के मामलों में तेजी आने और देशव्यापी बंद के बाद, सभी स्टैपल्स और जरूरी सामान के लिए मांग प्रभावित हुई है और विभिन्न सामान के निर्माता मांग पूरी करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।

ठप पड़ रहे देश के विनिर्माण संयत्र

पृष्ठ 1 का शेष

इस तरह, कुछ समय पहले तक केवल पश्चिम बांगल में ही इसका परिचालन हो रहा था। इमामी समूह के आदित्य वी अग्रवाल ने कहा,'पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले तक परिचालन हो रहा था, लेकिन श्रमिकां एवं परिवहन साधनों के अभाव में यहां भी परिचालन बंद करने की नौबत आ गई है।' लॉकडाउन के कारण ट्रक राज्य की सीमाएं नहीं लांघ पा रहे हैं और चालकों के अभाव में राज्य के भीतर भी ट्रकों की आवाजाही सीमित है। इससे स्टॉकिस्ट और वितरकों तक सामान की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। एक उपभोक्ता उत्पाद कंपनी के प्रवर्तक ने कहा,'अगर वितरकों से उत्पाद की मांग होने पर भी परिवहन साधनों के अभाव में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीजों से हमारे हाथ नकदी भी नहीं आ पा रही है।'देश के प्रमुख उद्योगों की हालत भी ठीक नहीं है। एक अग्रणी इस्पात उत्पादक ने कहा कि औसतन उनकी कंपनी को 500 ट्रकों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह कम होकर 20 रह गई है। इस कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, 'ट्रक चालक लंबी दूरी यत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सड़कों के किनारे सभी ढांबे बंद है।' कमजोर मांग और परिवहन साधनों के अभाव से कंपनी के संयंत्र में उत्पादन 40-50 प्रतिशत तक कम हो चुका है। संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या में भी 60-70 प्रतिशत तक कमी आई है।

> कमजोर मांग के कारण कंपनियों के संयंत्रों में उत्पादन 40 से 50 फीसदी घटा

मंगलवार को इस्पात सचिव बिनॉय कुमार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि देश में कई इस्पात संयंत्र कामगारों की कमी, कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़ीं दिक्कतों और तैयार इस्पात का परिहवन नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिवों से इस्पात संयंत्रों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाने का आग्रह किया है। सीमेंट कंपनियों में उत्पादन थमने की नौबत आ गई है। इन कंपनियों के संयंत्रों में मजदूरों की कमी और सीमेंट की ढुलाई नहीं होने से दिक्कतें पेश आ रही हैं।

ज्यादा खरीदारी से खाली हो रहीं दुकानें

कोरोनावायरस के भय से जल्दबाजी में अधिक सामान खरीद रहे हैं ग्राहक, दिल्ली तथा मुंबई की कई फार्मेसी पर भी हैंडवॉश, सैनिटाइजर तथा शैंपू का स्टॉक खाली हो गया

विवेट सुजन पिंटो और अर्णब दत्ता

मुंबई के सांताक्रूज तथा चेंबूर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में किराना स्टोर में फिलहाल सामान उपलब्ध है लेकिन बस थोड़ा ही। दिल्ली तथा गुरुग्राम जैसे शहरों में भी स्थित कोई खास अलग नहीं है। देश में लॉकडाउन के लंबा चलने की संभावनाओं के बीच आखिरी समय पर लोग ब्रेड, आटा, साबुन से लेकर नूडल्स तक लगभग सभी घरेलू सामान खरीद रहे हैं। सांताक्रूज क्षेत्र के एक दुकानदार सुरेश किरानेवाला का कहना है कि उनका सामान जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह कहते हैं, 'आमतौर पर मेरे स्टोर में आठ दिन के सामान का भंडार रहता है। लेकिन जबसे कोरोनावायरस का भय लोगों में फैला है, सामान बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन सामान मंगाना पड़ रहा है। शनिवार को ही नया स्टॉक आया है और मेरे पास केवल 24 घंटे का ही सामान शेष है।'

सुरेश के स्टोर से कुछ दूरी पर स्थित दूसरी दुकान, दर्शन किरानेवाला में पैकेट बंद आटा, बिस्किट और साबुन खत्म हो गए हैं। दर्शन कहते हैं कि उनके पास जो भी सामान उपलब्ध है वह उसे बेच रहे हैं और बाकी आपूर्ति आने का इंतजार कर रहे हैं। वह कहते हैं, 'मेरे पास क्या विकल्प है। इस समय ट्रांसपोर्ट बड़ा मुद्दा है। लॉकडाउन से कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।' मुंबई तथा दिल्ली की फार्मेसी भी हैंडवॉश, हैंड सैनिटाइजर तथा शैंपू के स्टॉक को भरने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा तथा दिल्ली में एफएमसीजी सामानों के कई वितरकों तथा खुदरा विक्रेताओं के साथ बातचीत से पता चला है कारोबारियों को रिटेल प्वाइंट्स पर सामान पहुंचाने या ले जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस समय पुलिस ने सड़कों पर बैरियर लगा दिए हैं तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है।

मुंबई में किराना स्टोर से सामान खरीदने के लिए कतार में खड़े ग्राहक
फोटो : कमलेश पेडणेकर

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएच कृष्णा कहते हैं, 'फैक्ट्रियां बंद हैं और वहां से वेयरहाउस, भंडारकर्ता, वितरकों तथा खुदरा विक्रेताओं तक सामान नहीं पहुंच रहा है।' वह कहते हैं, 'इसके चलते बिक्री प्रभावित होगी तथा छोटे कारोबारियों को यह नुकसान उठाना मुश्किल हो जाएगा।' मंगलवार को कोकाकोला इंडिया तथा नेस्ले इंडिया ने घोषणा की कि वे लॉकडाउन के चलते उत्पादन कम कर रहे हैं और कुछ जगहों पर परिचालन बंद कर रहे हैं। कोकाकोला ने बताया कि कंपनी कुछ इकाइयों पर ही परिचालन जारी रखेगी।

इसके अलावा, गोदरेज कंज्यूमर तथा आईटीसी जैसी कुछ दूसरी कंपनियां स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक वस्तुएं बनाने के लिए परिचालन जारी रखने की मांग कर रही हैं। ये कंपनियां बफर स्टॉक बना रही हैं और उत्पादों एवं पैकेज्ड सामानों की समयबद्ध एवं बाधारहित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने वेंडरों के साथ रणनीति पर काम कर रही हैं।

गुजरात के एक वितरक, अरुण पारिख का कहना है कि कई खुदरा कारोबारियों को अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह कहते हैं, 'एक तरफ बिक्री घट रही है वहीं खुदरा कारोबारियों तथा वितरकों को बिजली-पानी बिल, किराया, कामगारों का मासिक वेतन तथा कर्ज की किस्तें लगातार देनी पड़ रही हैं। जब आय कम हो तो ऐसे में इन चुनौतियों से पार पाना काफी आसान नहीं है।'

मंगलवार को सरकार ने घोषणा की है कि आयकर तथा जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 जून तक टाल दी गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन अगले कुछ दिनों में छोटे कारोबारियों को अधिक राहत देने की मांग वाली एक याचिका सरकार को सौंपेगी।

लॉकडाउन से छिना रोजगार

पृष्ठ 1 का शेष

लेकिन 100 किमी का पैदल सफर के बारे में पूछने पर नागर ने कहा, 'क्या कांवड़िया नहीं जाते हैं। नवरात्र शुरू हो चुके हैं। अपनी यात्रा में हम मंदिरों और गांवों में रुकेंगे। हो सकता है कि हमें लिफ्ट मिल जाए।' गौतमबुद्ध नगर की सड़कों के किनारे आपको बड़ी संख्या में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे और इनमें से सारे लोग वापस नहीं आएंगे। महेंद्र ने कहा, 'बहुत हो चुका, अब मैं गांव में कटाई में मदद करूंगा और वहीं रहूंगा। यहां कुछ नहीं रखा है।'सेंट्रल नोएडा के पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र अपनी टीम को निर्देश दे रहे हैं। उनका कहना है कि सख्त रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए लेकिन जो लोग मस्ती कर रहे हैं, उन पर कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस कई स्थानों पर खाना पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। हालांकि वह मानते हैं कि पुलिस के लिए हर समय संयम बरतना मुश्किल है।